हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 जुलाई, 1976

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूचि

वीरवार, 8 जुलाई, 1976

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 1
बहिर्गमन	(4) 11
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(4) 23
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4) 23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 24
कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन	(4) 26
गैर–सरकारी संकल्प	
सतलुज–यमुना लिंक नहर को मुकम्मल करने सम्बन्धी	(4) 27

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 8 जुलाई, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,

सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 14.00 बजे हुई ।

अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Loan given by the State Government to the Haryana State

Electricity Board

***1605. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount of loan given by the State Govt. to the Haryana State Electricity Board during the financial years from 1971-72 to 1975-76 'together with the condition imposed in respect thereof and the amount due from the Board as at present ?

State **Minister for Irrigation and Power** (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : A statement is placed on the Table.

STATEMENT

The loan given by the State Government to Haryana State Electricity Board during financial years 1971-72 to 1975-76 is as under : —

Year	Loan (Rs. in lacs)
1971-72	1185.65
1972-73	1904.58
1973-74	2515.19
1974-75	3076.44
1975-76	3654.57

The conditions imposed by Government varies according to the schemes for which the loan is sanctioned. However, general conditions imposed by Government are as under : —

(a) Loan will carry interest varying from 4.75%. to 6% per annum and shall be repayable in 12 years/15 years. (12 years in case of loan granted for thermo electric schemes and 33 KV works and below and 15 years loans granted for Beas/B.M.B. works).

(b) The principal and the interest shall be payable ii equal six monthly instalments on 30th September and 31st March, each year. The first ins- 1 talment of loan will commence three years after the drawal of the amount. In case of default of payment of any instalment, the amount of instal-ment will be carried over and added to the principal. The Government may charge penal interest for the instalment and

defaulting amount unless it is satisfied that the Board was unable to pay the instalment for reasons beyond its control. The penal interest shall be upto two times the rates of interest charged.

(c) In case of disposal of any assets for which the loan was advanced by the State Government, the loan shall be first charged on the disposal value of the assets.

(d) In case the loan is utilised by the Board for the purpose other than for which it was sanctioned by the State Government. it shall become repayable at once and the State Government may charge penal interest with respect to the amount utilised for the unauthorised purpose unless it is satisfied with the explanation which the Board may offer in this behalf.

The total amount of loan due from the Board upto 31-3-76 is Rs. 22,409.49 lakhs.

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, स्टेटमैंट तो मुझे अभी मिली है और मैं इसे पढ भी नही सका । इसमें दिया गग्ग है कि स्टेट गवर्नमैंट ने बिजली बोर्ड को 1971— 72 में 1,185.65, 1972— 73 में 1,904.5 8, 1973— 74 में 2,515.19, 1974— 75 में 9,078. 44 और 1975—76 में 3,854. 57 लाख रुपए लोन के रूप में दिए, तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह पैसा बोर्ड ने किस किस काम पर खर्च किया और इससे कितनी बिजली बढी?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः इसमें से बहुत सा पैसा कन्ट्रक्शन पर भी लगा है सतलुज ध्यान लिक जहां बिजली बन रही है, वहां भी लग रहा है, थर्मल प्लांट्स पर भी लग रहा है जैसे जैसे ये प्रोजैक्ट्स तैयार होते जाएंगे, वैसे ही बिजली बढ्ती जाएगी ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह पैसा अलग अलग कौन कौन सी स्कीम पर खर्च हो रहा है और उनमें से कौन कौन सी स्कीम पूरी हो चुकी हैंऔर कौन कौन सी अधूरी रही हैं '

सरदार हरमोहिन्दरं. सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब इन्होंने 5 साल का पूछा है । इसमें भाखड़ा–नंगल प्रोजैक्ट पर 5, 271 लाख, 33 के०वी० वर्कस और बिलो पर 4,568 लाख और थर्मो इलैक्ट्रिक स्कीम पर 2,088 लाखऔर इसीप्रकार व्यास प्रोजैक्ट पर 196 करोड लगा और इसी ढंग से जब पंजाब ओर हरियाणा बना, तो कुछ पैसा उधर से भी आया था । तो यह सारे का सारा पैसा बिजली बोर्ड को दे रहे हैं । बिजली बोर्ड जो प्रोजैक्टस की कंस–ट्रक्शन कर रहा है उससे हमारे हरियाणा में बिजली और इस्तेमाल होगी ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बिजली बोर्ड ने जितना लोन लिया है, उसमें से कितना पैसा उसने वक्त पर वापिस दे दिया है और कितना देना अभी बाकी है?

सरदार हरमोहिन्दरसिंह चट्ठा : इसमें कडीशनें लगी होती हैं । पहले तो वह कर्जा वापिस किया जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमैंट की गारन्टी नही होती उसके बाद प्रायरिटी उस के इंटैरस्ट पर होती है, उसके बाद दूसरा कर्जा देने की । लेकिन एक बात यह है कि हमारा बिजली बोर्ड खूब अच्छे ढंग से काम कर रहा है ।

मलिक सतराम दास बसरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो प्रोजैक्ट्स पहले शुरु किए गए थे और वे आज कम्प्लीट हो चुके हैं अगर वे आज शुरू किए जाते, तो उन पर कितने गुना खर्चा और ज्यादा आता?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः यह तो डिफैटं प्रोजैक्ट्स पर डिपैडं करता है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जब आज कल आम यह कहा जा रहा है कि कीमतें सस्ती हो गई हैं तो प्रोजैक्ट्स पर खर्चा ज्यादा क्यों होता है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, मैंबर साहब को यह पता होनाचाहिए कि मुलाजिमों और लेबर की तनख्वाह का कितना खर्चा आ रहाहै ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1616

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Jobs created under 20-Point Economic Programme

***1636. Chaudhri Mehar Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any jobs are being created under the 20-point Economic Programme for educated unemployed persons in rural areas ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दासगुप्त) : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण योजना है,—जिसका उद्देश्य रोजगार तथा प्रशिक्षण के अवसरों को बहाना है । इस योजना में अनुसूचित जातियो, पिछडे वर्गों, अल्प सख्यकों तथा विकलांग व्यक्तियों केलिए न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

प्रशिक्षण अधिनियम के अधीन वर्ष 1975—76 के दौरान कुल 3, 288 व्यक्तियों को लगाया गया था । इनमें से कुछ व्यक्तियों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है । इस समय प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षुओं की संख्या 3, 810 है । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वयं रोजगार दिलाने वाली योजनाओं के अधीन 6092 व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध करवाई गयीं । यह आंकड़े राज्य में रोजगार की कुल सम्भावनाएं उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित हैं। —ग्रामीण/शहरी क्षेत्रो में शिक्षित अशिक्षित व्यक्तियों के बारे में पृथक रूप से सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि इस योजना के अन्तर्गत अपने रोजगार की योजना भी शामिल है या इससे अलग है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अपने रोजगार सम्बन्धी हमने प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत सारे प्रदेश में एक अभियान चलाया है और उस अभियान का जो नतीजा निकला वह यह है कि 6,092 व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की सम्भावनाएं उपलब्ध करवाई गयी ।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि ये जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निकलेंगे, क्या उनके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है कि वे बेकार न फिरें?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय कल या परसों. इसी प्रकार का एक प्रश्न था जिसका जवाब देतेहुए हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बताया था कि हम इस प्रकार को संशोधन करने जा रहे हैं कि जिस जगह ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ,उसी जगह इनको काम भी दिया जाए ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि खड्डियों के काम या इसी प्रकार से दूसरे छोटे कामों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, रूरल आर्टिजन्ज को काम देने के लिए हमने पूरा प्रबन्ध किया है ।

आपने सुना होगा कि पिछली दिनों हमने एक नई कार्पोरेशन बनाई है, जिसका नाम है हैंडल्म ऐंड हैं–दीं क्राफ्ट कार्पोरेशन । इस कार्पोरेशन के तहत जितने भी हमारे वीबर्ज या जुलाहे जो गांवों में बैठे हैं उनको हम कच्चा माल भी देगे, आजकल के आधुनिक औजार काम करने के लिए देंगे, वर्किंग कैपिटल भी देंगे और उनके तैयार माल को बेचने का भी पूरा इन्तजाम करेंगे। इसके अलावा हमने कई स्थानों पर हैंडलूम की ट्रैनिंग देने के लिए सैन्टर भी बोले हैं ।

राव बंसी सिंह : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि को–आप्रेटिव हैक्टर के अन्दर भी ऐसे कोई प्रबन्ध किए जा रहे है जिससे लेबर कोकाम दिया जाए?

श्री बनारसी दास गुप्त : को–आप्रेटिव सैक्टर के अन्दर भी अध्यक्ष महोदय हमने ऐसा प्रबन्ध किया है जो रूरल आटिजन्ज हैं, उनको ऋण की सुविधा दी जाए और यह जो हमने नई कार्पोरेशन स्थापित की है, उसको भी हम ने आदेश दिया है कि सहकारी विभाग के सहयोग से इस काम को आगे चलाएं ।

श्री अमर सिंह : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि जैसे कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब ने दो करोड़ के प्रोजैक्ट के बारे में सैन्टर की मदद के बारे में बताया था तो उस पैसे को कब से खर्च किया जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्त : यह सैन्ट्रल प्रोजैक्ट है जो हरियाणा प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है और हम उनसे प्रार्थ ना करेगे कि वे यह स्कीम जल्द से जल्द चालू करे ।

चौधरी अमीर चन्द कक्कडः क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि जो आर्टिजन्ज का तैयार खुदा माल होगा क्या उसको सरकार खरीद कर लेगी, या बिकवाने में मदद करेगी?

श्री बनारसी दास गुप्त : अभी इसके लिए पूरी योजना तैयार नही हुई है । हम इन लाइन्ज पर विचार कर रहे है कि जितना भी उनका माल होगा, वह हम ले लें और उनको उसकी 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत या 80 प्रतिशत कीमत अदा कर दें और जब वह माल बिक जाए, तो वह बाकी कीमत भी अदा कर दें ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि गांवों में जितने चमार औंर लोहार हैं ऐसे जो दस्तकारी करते है, उनके लिए भी कोई योजना बनाई हैकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जितने भी रूरल आर्टिजंन्ज हैं, चाहे वे लोहार का काम करने वाले हों, चाहे लकड़ी का काम करने वाले हों, चाहे चमडे का काम करने वाले हों और चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हों, उन सबको पूरी सहायता दी जाने वाली व्यवस्था इस कार्पोरेशन के अन्दर है ।

Construction of Approach Roads

***1666 Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the time by which the following approach roads are likely to be completed -

1. From G.T. road to Lalyani and Travari via Bhaini Khurd ;

2. From Nilokheri-Karsa road to Tigri, Isahakpur, Salappur and Kurukshetra via. Ahbla ;

3. From Salarpur to Sonehri ;

4. From Sitamarh on Karnal-Kaul road to Mohri and Bahola ;

5. From Nilokheri-Karsa road to Bhookapur ;

6. From Nilokheri-Karsa road to village Budhera ;

7. From Nigdhu on Nilokheri-Karsa road to village Pastana ;

8. From village Kirmich to Shamshipur ;

9. From village Kirmich to Barwa ;

10. From Janjari-Lalyani road to village Sultanpur ;

11. From Uchana to Rupanpur (Budhanpur) ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(i) Roads at Sr. No. 1, 2, 7 and 11 are complete except gaps of 0.75 Km., 0.4 km., 0.5 km., and 1.10 km.

respectively. These gaps will be completed during the current financial year.

(ii) On roads at Sr. No. 3, 4, 5, and 6, only earth work has been done either in full or part length. But no work has been started so far on roads length at Sr. No. 8 and 10. Their completion will depend on the availability of funds.

(iii) Roads at Sr. No. 9 forms a duplicate link which according to the present policy of the Government cannot be constructed at this stage.

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह बात उनकी जानकारी में है कि इन गैप्स के कारण ये सारी छर्ड्के बेकार पड़ी हैं, करन्ट फाइनैंशियल ईयर तो बहुत दूर है क्या आप उनको जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, my reply is clear that the Government do feel the necessity of filling these gaps. But as **I** have stated they will be completed by the end of this year.

श्री के ० एन० गुलाटी : स्पीकर साहब, फरीदाबाद के डबुआ ब्लाक में जो सड़क नवादा से डबुआ को लिंक करती है, उस पर जिला परिषद् के वक्त के पत्थर पड़े हुए हैं, क्या मन्त्री महोदय उस लिंक रोड को जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, this supplementary does not arise out of this question. But so far as the approach road is concerned, if it falls within the policy

of the Government that where earth work is done and where stone material is lying, we would certainly give priority to such roads.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, जो इन्होंने कहा है कि दूसरे लिंक होने की वजह से वे अभी नहीं बन सकती । क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनकी जरूरत को महसूस करते हुए दूसरे लिंक की शर्त को हटाकर उनको बनाने की कोशिश करेंगे?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : स्पीकर साहब, अभी तो यही पालिसी है कि वहां हम दूसरी लिंक रोड नहीं बनाते ।

Loans outstanding against the Cooperative Societies

***1669. Rao Dalip Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Cooperative Societies in the State against which loans of Cooperative Banks are outstanding and the amount involved therein as at present ; and

(b) the total number of Cooperative Societies against which the above said loans are outstanding for more than five years ?

गृह एवं स्वास्थय राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी):

(क) 28– 5– 76 को 5, 762 सहकारी समितियों के जिम्मे सहकारी बैकों का 43.42 करोड़ रुपए ऋण के रूप में था । उसी दिन 13. 93 करोड़ रुपए अतिदेय था ।

(ख) 28– 5–7 8 को 1, 257 सहकारी समितियों के जिम्मे पांच वर्ष से अधिक समय का अतिदेय ऋण 1.62 करोड़ रुपया था ।

राय दलीप सिंहः क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि ऐसी सोसायटीज कितनी हैं, जिनके जिम्मे 10 साल से ज्यादा के कर्जे बकाया हैं?

श्रीमती शारदा रानी : 5 साल सेज्यादा जिनके जिम्मे कर्जे हैं, ऐसी 1,257 सहकारी समितियां हैं ।

राव' बंसी सिंह : स्पीकर साहब, जो इतनी बड़ी भारी रकम उनके जिम्मे है, उसको कब तक रिकवर कर लेंगे?

श्रीमती शारदा रानीः स्पीकर साहब, उनको रिकवर करने के लिए काफी तेजी से कदम उठाए जा रहे है । इन ओवर डयूज की रकम काफी कम हो गई है और इस साल जो जुलाई के एंड में हमें रिकवरीज के आंकड़े मिलेंगे उसमें परसैटेज काफी कम हो जाएगी, और बहुत कम कर्जे ओवरडयू रह जाएगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, यह जो 1, 257 सोसायटीज मन्त्री महोदया ने बताई हैं जिनके कर्ज ओवर–क्यू हैं, वे किस–किस जिले में हैं?

श्रीमती शारदा रानी : ये सभी जिलों में हैं ।''

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, अगर गर्ग साहब रिंकवरी की गारंटी दे दें तो हम उनको जिलों की सोसायटियों की लिस्ट दे देगे ।

श्री गौरी शंकर: स्पीकर साहब, जो ये कर्जे हैं, इनके ओवर डयू होने की क्या वजह है? क्या यह महकमे के अफसरों के फाल्ट की वजह से ऐसा हुआ है और अगर ऐसा हुआ, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया है कि उन्होंने गलत सोसायटियों को रुपया क्यों दिया?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब इसमें कसूर तो सब का है । इसमें सन्देह नहीं कि कई कर्मचारी कसूरवार होंगे जहां–जहां, जिन–जिन कर्मचारियों का कसूर साबित हो रहा है, सरकार ऐक्शन ले रही है । कई केसिज रजिस्टर भी हुए हैं ।

राव बंसी सिंह : स्पीकर साहब, यह जो 1 257 सोसायटीज बताई गई हैं जिनके जिम्मे इतनी भारी रकम कर्जो की ओवर–डयू है, इनमें एग्रीकलचरल सोसायटीज के जिम्मे कितनी रकम ओवर–डयू है और नान–ऐग्रीकल्चरल सोमायटीज की कितनी ओवर–डयू है?

श्रीमती शारदा रानीः स्पीकर साहब यह जो सोसान्टीज है इनके जिम्मे 2 8– 5– 78 तक टोटल अमाऊंट 1.62 करोड़ ओवर डयू थी जिसमें से जैसा कि मैंने पहले बताया कि काफी रिकवर हो चुकी है और इसकी परसैटेज बहुत कम हो गई है । एग्रीकल्चरल को आप्रेटिव सोमाराटीज के अगेस्ट 12 लाख 34 हजार ओवर डयू है ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि रिकवरी की परसैटेज क्या है और अब तक कितनी रिकवरी हो चुकी है?

श्रीमती शारदा रानी : इस साल की फिगर्ज तो हमारे पास नही. है, लेकिन जो ओवर– डयू रकम है, वह टोटल आउटस्टैडिग रकम की 32 प्रतिशत है ।

श्री अमर सिंह : वजीर साहिबा ने बताया है कि 1,257 सोसायटीज के जिम्मे 1.62 करोड़ रुपया है । ऐसी कितनी सोसायटीज है जिनके वेयर अबाउट नोन नही है ।

श्रीमती शारदा रानी : सभी सोसायटीज के वेयर अबाउट्स मालूम है ।

श्री गौरी शंकरः क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि उन–सोसायटीज में जिनके खिलाफ लोन्ज ओवर–डयू हैं, उनमें किस–किस आदमी के खिलाफ केस कराया है?

श्रीमती शारदा रानी : डिटेल्ज तो हमारे पास नही, लेकिन काफी केसिज है जो हमने रजिस्टर करवाए है ।

चौधरी पौर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएगी कि इन सोसायटीज मे कोई हरिजन सोइसयिटीज भी हैं, अगर हैं तो हरिजन मैंबरों ने जो कर्जे ले रखे है क्या कर्जे गवर्नमैट उनको माफ कर देगी, जैसा कि देहातों में लौगों ने जो प्राइवेटली कर्जे ले रखे थे,'वे माफ कर दिए है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों को सहकारी कर्जे माफ करने का प्रोविजन कही नही है, 'न हीं कोई आदेश है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, जो केस रजिस्टर कराए गए हैं उनको साल भर से ऊपर हो गया है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि उन पर कब तक कार्यवाही हो जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, यह कोर्ट का मामला है, क्योकि केस रजिस्टर कराने के बाद कोर्ट के हाथ में बात चली जाती है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री साहिबा बताने की कृ पा करेगी कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं,उनके कर्जे माफ करने का कोई विचार है?

श्री शारदा रानी : ऐसा कोई विचार नहीं है । जहां तक होगा, वहां तृक वसूली ही की जाएगी

श्री निहाल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि जो आउटस्टैंडिंग लोन्ज हैं । इनके बैड डेटस कितने हैं जो रिलाईज हुए और रोईट आफ करनें पडे हो?

श्रीमती शारद रानी : अभी तक इस प्रकार के कोई कर्जे राईट आफ नहीं किए है । विघ्न

श्री अमर' सिहं : क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंसी कि उनके नोटिस में यह बात हैकि केस रजिस्टर होने के बाद को–आप्रेटिव सौसायटीज का रिकार्ड चुकि नहीं मिलता, इसलिए फरदर कार्यवाही नही होती ?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यहबात, ठीक है । कई बार ऐसा होता है कि केस रजिस्टर केरवा दिया जाता और और जो बहुत बड़ा डिफाल्टर है, वह हमारे कुछ कर्म–चारियों से सांठ गांठ कर लेता है और वे रिकार्ड प्रोडयूस नही करते, केस पूरा नहीं होता । अब इस बारे मे जो हमनें सख्त कार्यवाही कर दी है जो कर्मचारी ऐसी बातों में इनवाल्वड होता है, उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाता है

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, मैं मन्डी साहिबा से आपकी वसातत से एक बात पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में

कितनी को–आप्रेटिव सोसायटीज ऐसी है जहां गबन हुआ है और क्या ऐक्शन लिया गया है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, जिन सोसायटीज के अगेंस्ट कर्जे 5 साल से अधिक आउट स्टैडिंग हैं, उनका नम्बर मैंने 1, 257 बता दिया है और गबन का कोई केस हमारे पास नहीं है ।

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि कितनी सोसायटीज ऐसी हैं, जिनका आज तक आडिट नही हुआ और उसका कारण क्या है?

Mr. Speaker : Order please. Not a supplementary to this question please.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने अभी जवाब दिया कि हरिजनों का कर्जा छोड़ने की कोई सम्भावना नहीं है । क्या वे बताने की कृपा करेंगी कि कर्जा नहीं तो सूद छोड़ देंगे?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी नही छोड़ेंगे ।

Wholesale rates of Soft Coke

***1675. Chaudhri Peer Chand :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the month-wise wholesale rate of soft coke

fixed by the State Government during the financial years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 to-date ;

(b) whether Government is aware that any of the Coal Agents in Hissar District have charged rates over and above the rates referred to in part (a) above together with the names of such Coal Agents; if so, action taken by the State Government against the Coal Agent;

(c) whether the wagons are allotted to the Coal Depot-holder by the State Government or by the District Food & Supplies Controller together with the criteria of allotment ;

(d) whether the District Food & Supplies Controller is competent to allot wagons of soft coke to the Coal Agent for free sale in the market or to the coal depot holders ; if so, the circumstances in which wagons are allotted to the Coal Agent for free sale ; and

(e) whether the Coal Depot-holder is liable to pay the price of soft coke as per Railway Receipt or actual weight of the soft coke supplied to him ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) No month-wise wholesale rates of soft coke were fixed by the State Government during the financial years 1974-75, 1975-76 and 1976-77.

(b) The time and labour involved in collecting the required information will not be commensurate with any

possible benefit to be obtained.

(c) Coal wagons are allotted to the Coal Depot-holders by **the** District Food & Supplies Controller of the District in consultation with the District Magistrate. The allotment is done in an alphabetical order.

(d) The District Food & Supplies Controller is competent to allow free sale of soft coke in consultation with the District Magistrate concerned, in the event of there being no demand of soft coke.

(e) Payments to Coal Agents/middlemen are to be made by the Coal Depot holders on the basis of weight and freight as indicated in the Railway Receipts.

बहिर्गमन

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय मै निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रश्न पूछने वाले के जवाब ही पल्ले न पड़ा हो तो वह सप्लीमैंट्री क्या पूछेगा? (विध्न)

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : यह भाषा बैन नहीं है । मैं इसमें ही जवाब दूंगा । जो न समझ सके न समझें । (शोर) मौखरी पीर चन्द फिर तो मैं वाक आउट करता हूं । (शोर)

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : कर जाओ । (शोर)

(इस समय चौधरी पीर चन्द जी सदन से बाहर चले गए)

चौधरी शिव राम वर्मा: अंग्रेजी पर पाबन्दी लगने के बाद ही आप इसे बोलने से हटेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है । अपने आप अभी से हिन्दी में उत्तर देना उचित रहेगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दासग गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि कई हमारे साथी प्रश्न भेजते हें इंगलिश में और जवाब चाहते हैं हिन्दी में । आयंदा के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस भाषा में क्वैश्चन आए गा उसी भाषा में जवाब दिलाएंगे ।

चौधरी शिव राम वर्मा : चौधरी पीर चन्द ने तो इंगलिश में नहीं भेजा होगा ।

श्री बनारसी दास गुप्त : किसी से लिखवा कर भेज दिया होगा ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Industrial Disputes

***1606. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Transport **be** pleased to state-

(a) the district-wise number of Industrial disputes referred to the Industrial Tribunal, Haryana and Labour Court, Haryana, during the, year 1975-76 by the State Government under the Distputes Act, separately

(b) the district-wise total majer of cases out of those referred to in part (a) above, settled by compromise

decided in favour of and against, the workmen by the Industrial Tribunal and Labour Court, sepatately during the period as referred to in part (a) above ; and

(c) the total number of disputes lying pending to-date as also the 'pending cases as on 31st March, 1974 with the Industrial Tribunal and Labour court

परिवहन मन्त्री (श्री के०एल०पोसवाल) : एक विवरण पत सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण पत्र

(ए)		कोर्ट का नाम	
		उद्योगिक न्यायाधिकरण	श्रम न्यायालय
(1)	रोहतक	4	38
(2)	गुडगाव	164	
(3)	जीद		1
(4)	सोनीपत	3	9.
(5)	करनाल	2	4
(6)	'कुरुक्षेंत्र		1

(7)	भिवानी	7	12
(8)	अम्बाला	8	57
(9)	हिसार	1	1
(10)	महेन्द्रगढ़		
(11)	सिरसा		
	योग	187	123

(बी)		उद्योगिक न्यायाधिंकरण			श्रम न्यायाधिंकरण		
		समझौते द्वारा निर्मित	श्रमिक पक्ष में निर्मित	श्रमिक के विरुद्ध निर्णित	समझोते द्वारा निर्णित	श्रमिक के पक्ष में निर्णित	श्रमिक के विरुद्ध निर्णित
1	अम्बाला	4	1	1	5	1	3
2	भिवानी	2	1				1
3	रोहतक		1	2		1	4

4	गुड़गावां	3	2	11			
5	करनाल						1
6	सोनीपत					1	2
7.	हिसार						
9	सिरसा						
10	महेन्द्रगढ						
11	कुरुक्षेत्र						
	योग	9	5	14	5	3	11

(सी)	कोर्ट का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
	31 – 3– 74	31 – 5– .76
उद्योगिक न्यायाधिकरण	228	197
श्रम न्यायालय	284	148

श्री के ०एन० गुलाटी : क्या मन्त्री जी यह बताएंगे कि जितने डिस्प्यूटस पड़े हैं उनको निबटाने केलिए, फैसला करने के

लिए केवल एक ही इंस्टिच्यूशन काफी है? अगर काफी नहीं है, तो क्या दूसरी लेबर कोर्ट स्थापित की जाएगी?

श्री के०एल० पोसवाल : स्पीकर साहब, हम एक एडिशनल लेबर कोर्ट के लिए भी तजवीज कर रहे हैं ताकि अगर ज्यादा काम हो, तो उसे वह निबटा सके । (विध्न)

तारांकित प्रश्न संख्या 1617

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Bridge over Bari Khalasi

***1647. Chaudhri Shiv Ram Verma : Will the Chief Minister be pleased to state—**

(a) the time by which the bridge over Bari Khalasi near village 'Hathlana' in Nissang Block is likely to be constructed ; and

(b) the time by which the Janjhari Drain is likely to be completed ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) The construction of the bridge will be decided according to the inter-se priority of the various Flood Control and Drainage Works subject to availability of funds.

(b) Janjhari Link Drain has already been

excavated.

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में है कि जिस डेरन के ऊपर यह पुल बनाने के बारे में मैंने पूछा है, उसके बारे में पंडित रामधारी गौड़ जब मन्त्री थे, वे भी वहां जाकर वायदा करके आए थे और उसके बाद चौधरी गोवर्धन दास भी वायदा करके आए थे, अगर है तो उसका क्या बना?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि इनका सवाल इनकंप्लीट है । इनको ड्रेन का नाम बताना चाहिए था ।

चौधरी शिव राम वर्माः ड्रेन वहां एक ही है ।

सरदार हरमोहिन्दर सिंह : चट्ठा क्या नाम है?

चौधरी शिव राम वर्मा : नाम लिखा है ।

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, सरकार ने यह फैसला किया है कि जो भी ड्रेन्ज के ऊपर पुल हैं वे हम बनाएगे, लेकिन उन ड्रेन्ज के ऊपर पुल बनाने के लिए चार करोड रुपए लगतेहैं । इनकी प्रायरिटी बहुतलों है । अगर हमारे मन्त्रीगण ने वायदा किया है तो उससे हम मुन्कर नही होते लेकिन उनकी प्रायरिटी बहुत पीछे है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि यह ड्रेन 15–20 साल से बनी हुई है जो गांव इसके पास पड़ते हैं, उनका रकबा ड्रेन की दूसरी साइड पर पड़ता है, स्कूल भी ड्रेन की दूसरी तरफ ही पडता है, इस कारण से गांवों के लोगों को काफी दिक्कत है, क्या वहां पर पुल बनाने में प्रायरिटी देगे?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, सभी गांवों में ड्रेन के दूसरे साइड पर लोगों की जमीनें पड़ती हैं । इस तरह से तो सारी ही ड्रेन को पुलों से छापना पड़ेगा ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मैं महकमे को इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि झझेडी लिंक डेर न को मुकम्मल कर दिया है परन्तु फिर भी मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसको पहले मुकम्मल क्यों नही किया गया? इसका क्या कारण है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, झझेडी ड्रेन इसलिए पहले मुकम्मल नहीं हो सकी थी, क्योंकि इनके गांव के लोगों ने सारी ड्रेन को काश्त कर लिया था । अब उनसे ड्रेन को छुडवाया है, तो अब कम्प्लीट कर दी है ।

Water Supply Schemes

***1670. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the district-wise total number of villages provided with Water Supply Schemes in the State to date;

(b) the district-wise total number of villages where the water is brackish in the State ; and

(c) the time by which the drinking water is likely to be supplied to the villages mentioned in part (b) above ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी) : वान्छित सूचान का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(क) राज्य में जिलावार ग्रामो की संख्या (up to date) जिनमे जिला वितरण सुविधाए प्रदान की जा चुकी हैं निम्न अनुसार है : ––

क्रमांक	जिले का नाम	(ग्राम संख्या जिनमे आज तक जल वितरण सुविधाएं पहुंचाई गई हैं?)
1	हिसार	67
2	भिवानी	257
3	गुडगावां	108
4	जींद	40

5	महेन्द्रगढ़	142
6	अम्बाला	150
7	करनाल	3
8	कुरुक्षेत्र	11
9	रोहतक	50
10	सोनीपत	6
11	सिरसा	40
	कुल	878

(ख) जिलावार कुल ग्रामों की संख्या का व्यौरा जिनमें पानी खारा है, निम्नानुसार दिया जाता है :–

क्रमांक	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या, जिनमें पानी खारा है ।
1	महेन्द्रगढ़	683
2	भिवानी	464
3	गुडगावां	741

4	रोहतक	431
5	अम्बाला	253
6	हिसार	382
7	जींद	278
8	करनाल	45
9	कुरुक्षेत्र'	41
10	सोनीपत	246
11	सिरसा	317
	जोड़	3,879

(ग) भाग 'ख' में दिखाए गए । ग्रामों में जल वितरण सुविधाएं प्रदान किए जाने की तिथि सुनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

राव दलीप सिंह : मंत्री महोदया ने बताया है कि सारे हरियाणा में 3879 गांवों में पानी पीने के काबिल नहीं है और उन्होंने यह भी बताया हैकि 878 गांवोंको पानी दिया गया है, तो मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि बाकी गांवों में कब तक पानी दे दिया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी गांवों को पानी दे दिया जाए लेकिन सब गांवों को पानी देने में पैसा बहुत लगता है । हमारे पास इतना पैसा नहीं है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 29 करोड़ रुपया मांगा था लेकिन उसमें से 6 करोड़ रुपया मिलने की उम्मीद थी जिसमें से दो–अडाई करोड़ अभी तक मिला है ।

राय बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदया डिस्ट्रिक्ट वाइफफिर्ग्ज देंगे कि सन 1975–76 में कितने–कितने गांवों को पीने का पानी दिया गया?

श्रीमती शारदा रानीः अब तक की डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर्ग्ज इस प्रकार हैं :–

हिसार में	67 गांवों को
भिवानी में	257 गांवों को
गुडगांवा में	106 गांवों को
जींद में	40 गांवों को
मोहिन्दरगढ में	142 गांवों को
अम्बाला में	150 गांवों को

करनाल में	3 गांवों को
कुरुक्षेत्र में	11 गांवों को
रोहतक में	58 गांवों को
सोनीपत में	8 गांवों को
सिरसा में	40 गांवों को

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि जो वाटर सप्लाई स्कीमें चालू की जाती हैं, ये केवल उन्हीं गांवों में चालू की जाती हैं जहां खारी पानी होता है? क्या उन गावों में भी चालू की जाती हैं जहां पर मीठा पानी होता है?

श्रीमती शारदा रानी : वाटर सप्लाई स्कीम उन एरियाज में चालू की जाती हैं जो सब–मौनटेनैन्स हैं या जहां पानी बहुत दूर से लाना पड़ता हो या ऊंची–नीची जगहें हों । सब–मौनटेनैस एरियाज में हमने काफी गांवों में पानी दिया है ।

श्री गौरी शंकरः क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि जीन्द जिले में बहुत थोड़े गांवों में पीने का पानी दिया गयाहै यानी केवल 40 गांवों को ही दिया गया है? तो मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इस साल और ज्यादा गांवों को पानी दिया जायेगा?

श्रीमती शारदा रानी : दूसरे जिलों के मुकाबले में तो जीन्द जिले की ज्यादा पर सैन्टेज है । जीन्द जिले में तो केवल 278 गावों में खारी पानी है जिनमें से 40 गांवों को मिल गया है । जीन्द जिले में तो बहुत कम गावों में खारी पानी है ।

चौधरी अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगी कि सन 1976–77 में कितने गांवों को पानी दिया जायेगा और खासतौर पर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कितने गावों को दिया जायेगा?

श्रीमती शारदा रानी : पानी देना तो पैसे पर डिपैन्ड करता है । जितना ज्यादा 'पैसा मिलेगा उतने ही ज्यादा नावों को पानी दे सकेंने । जैसे कि उम्मीद है कुल 100 या 125 गावों को हम पानी देने में सफल हो जायेंगे ।

चौधरी रिजक रामः क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन गावों में खारी पानी की प्रोबलम है, मीठा पानी नहीं मिलता है, उन गावों को पानी देने में कुल कितना खर्च होगा, क्या इसका एस्टीमेट लगाया है?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, आज से तीन–चार साल पहले हमने एस्टीमेट लगवाया था कि सारे गावों को मीठा पानी सप्लाई करें जिनमें खारी पानी है तो 80 करोड़ रुपये भू एस्टीमेट बनता था । अब मेरा ख्याल है कि 10– 15 करोड़ बढ़ गया होगा यानीं 90–95 करोड़ हो सकता है ।

चौधरी रिजक रामः क्या मन्त्री महोदय बतायेंमें कि नहरों के पक्का करने से और वाटर कोर्सिज के बैक्स पक्का करने के कारण सीपेज का पानी जमीन में कम जाने की वजह से और कई सालों से बरसात कम होने की वजह से उन एरियाज में जहां यह प्रोबलम नहीं थी वहां भी खारी पानी की प्रोबलम पैदा हो गई है ।

श्री बनारसी दास गुप्त : वैसे तो यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता परन्तु यह बड़ी अच्छी इन्फर्मेशन मांगी गई है जो मैं यह सदन के सामने रखना चाहता हूं । यह बात चौधरी साहब की बिल्कुल ठीक है कि पिछले कई सालों तक ड्राई साइकिल चलने की वजह से जहां सब–सायल वाटर मीठा था वहां सीपेज न होने की वजह से वाटर टेबल भी नीचे चला गया और पानी का स्वाद भी बिगड़ गया । तो जहां तक मैं समझता हूं कि पहले जो सर्वे करवाया था और जिन गावों के लिए एस्टीमेट बनवाया गया था उन गावों में नए गांव जिनका पानी खारी हो गया शामिल नहीं थे ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि करनाल जिले में भी पानी का स्तर नीचे जाने के कारण पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है? क्या करनाल के कुछ गांवों में भी यह योजना चालू की जायेगी?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, करनाल जिले में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई हो, ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है । वहां का वाटर टेबल नीचे जरूर हो गया है लेकिन पीने के पानी की समस्या बन गई हो, ऐसी बात नहीं है ।

चौधरी रिजक रामः क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो कारण उन्होंने बतायें हैं कि वाटर टेबल कम होने की वजह से या दूसरे कारणों से कुछ विलेजिज में यह समस्या बढ़ रही है । क्या इस लाइट में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट से दूसरी ऐजेन्सी से दुबारा सर्वे करवा कर इस बारे में मालूम करेंगे कि कोई ऐसे नये गांव भी हैं जिनमें यह–समस्या पैदा हो गई है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, ऐसा सर्वे करवायेंगे कि कितने ऐसे नये गांव हें जिनमें पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : इन्होंने बताया है कि पैसे की कमी के कारण सभी जगहों पर पीने का पानी जल्दी नहीं दिया जा सकता लेकिन हमारे अपने अम्बाला जिले में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पानी सूख गया है तो क्या उन जगहों पर एम० आई० टी० सी के सरकारी ट्यूबवैल्ज से पानी देने का प्रबन्ध करेंगे?

श्रीमती शारदा रानीः इसी बात का उत्तर कल मुख्यमन्त्री जी ने दिया था कि करेंगे ।

राय बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ जो कि बैकवर्ट एरिया है और वहां पर खारा पानी है, उस बैकवर्डनैस का ख्याल रखते हुए 1976– 77 के अन्दर कितने गांवों को पानी देने की स्कीम बनायी जायेगी?

श्रीमती शारदा रानी : यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते लेकिन वहां कुछ कन्टीन्यूस स्कीमें हैं जिनको पूरा करने की कोशिश की जायेगी । अब तक 142 गांवों को पानी दिया जा चुका है ।

श्री बिहारी लाल वाल्मीकि : हसनपुर में मुख्य मन्त्री महोदय, जब पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर थे, वाटर सप्लाई स्कीम का एलान करके आये थे, तो क्या एक–दो महीने में वह स्कीम पूरी हो जाएगी ताकि इनके दोबारा जाने से पहले ही वह स्कीम पूरी हो जाये?

श्रीमती शारदा रानी : हसनपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी है और वहां के लोगों ने अभी तक पैसा जमा नहीं करवाया । नोटिफाइड एरिया में गवर्नमैंट की कोई खास कन्ट्री– व्यूशन नहीं होती सिवाए इसके कि कुछ लोन या सबसिडी दे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : साहलावास में कई स्कीमें चल रही हैं और मंत्री महोदया उनका उद्घाटन भी करके आयी हैं । तो मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जितनी भी वहां स्कीमें चल रही हैं क्या उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय इनका मतलब असदपुर खेड़ा की स्कीम से है । मैं ने उसकी फाउन्डेशन रखी है । उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जायेगी ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि नारायणगढ कांस्टीटयूऐसी में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पानी खारा है और आदमियों तथा पशुओं को बड़ी परेशानी है क्या ऐसे गांवों को पानी देने में कोई प्रायरिटी दी जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर पानी की कठिनाई है जो उन गांवों की स्थिति रहेगी वही इनके गावों की स्थिति रहेगी । जब पैसा मिलेगा तो इनके गांवों को भी पानी दे दिया जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : अध्यक्ष महोदय, लाडवा में वाटर सप्लाई तथा सिवरेज दोनों स्कीमें हैं और कमेटी ने आपकी डिमान्ड के मुताबिक पैसा जमा करा दिया है लेकिन आपकी तरफ से ग्रान्ट नहीं मिल रही है जिसकी वजह से काम रुका पड़ा है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि वहां पर कब काम शुरू हो जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, अकेले लाडवा की सूचना तो मैंने मंगाई नहीं है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : स्पीकर साहब, चौधरी बसो लाल मेरी कांस्टीचुऐंसी में गए थे और उन्होंने वायदा किया था कि एक साल के अन्दर चिमनी ढराना की वाटर सप्लाई की स्कीम पूरी कर दी जाएगी क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या उनका वायदा पूरा किया जाएगा?

श्री बनारसी दासगुप्तः स्पीकर साहब, चौधरी बंसीलाल के जितने वायदे है उन सब को पूरा करेंगे ।

राव अभय सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगीं कि रिवाडी के लिए वाटर सप्लाई की स्कीम सैंक्शन हो चुकी है और उसके लिए रुपया भी अलाट हो गया है क्या उसको जल्दी चालू करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, राव अभय सिंह ठीक कहते हैं कि रिवाडी में पानी की समस्या बड़ी कठिन है । अभी पिछले दिनों कुछ फण्डज सरकार ने मन्जूर किए थे और एल० आई० सी० से लोन लिया गया था जिससे कि वहां वाटर सप्लाई के लिए पानी उपलब्ध किया जाए । साहबी नदी वहां से नौ मील के फासले पर बहती है । वहां ट्यूबवैल लगाए गए हैं, उस पानी को पाइप के द्वारा कैरी करके लाया गया है । ऐग्जिसटिंग पाइप्स की कैपेसिटी कम है और शहर की आबादी काफी बढ़ गई है । इस लिए पैरेलल पाइप लाइन डालने की कई लाख रुपए की स्कीम मन्जूर की गई थी लेकिन अब एक नई बात

पर विचार किया जा रहा है । अब यह सोचा जा रहा है कि वहां वाटर सप्लाई, कैनाल बेसिज पर की जाए क्योंकि जलाहर लाल नेहरू कैनाल का पानी इस साल वहां शहर के नजदीक पहुंच जाएगा और अगले साल हम रिवाडी शहर को जरूर पानी देने जा रहे हैं । इसलिए यह सोचा गया है कि यह पैसा इस वक्त न खर्च किया जाए ।

श्री रामधारी गौड़ : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि सब जगह पर ज्यादा गांवों को पानी दिया गया है और सोनीपत में सिर्फ छः गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम चालू है । गोहाना में 75 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां पानी उपलब्ध नहीं है ।

Mr. Speaker : What is the question ? You are giving information. You are not seeking information.

श्री रामधारी गौड़. : स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह था कि हर डिस्ट्रिक्टमें बहुत ज्यादा गांवों में वाटर सप्लाई की स्कीम्ज चालू हैं लेकिन सोनीपत में सिर्फ छरू गांवों को पानी दिया गया है इसका क्यों कारण है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सोनीपत में परसेन्टेज और जिलों की निस्बत कम है । उन जगहों पर पानी देने की कोशिश की गई है जहां पर पानी की ऐक्यूट सिक्येरसिटी है, लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है या बहुत ज्यादा खारा पानी है । इनके यहां ऐसी कोई समस्या नही है ।

श्री के०एन० गुलाटी : अध्यक्ष महोदय, शाहपुर खुर्द जो बल्लभगढ के पास है वहां की वाटर सप्लाई स्कीम कम्पलीट है, पाइप लाइन भी बिछ गई है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि वहां जाने से पहले उस स्कीम को चालू कर दिया जाएगा?

Mr. Speaker : Order please. This is not a supplementary. You cannot advance arguments.

चौधरी अब्दुर रजाक खां : स्पीकर साहब, मेरे यहां रावली बांध और कामेडा बांध के पास जो गांव लगते हैं और उन गांवों के लोग जहांसे पानी लाते हैं वह जगह बांध के अन्दर आ गई है और बरसात के दिनों में लोगों को पड़ोसी गांवों से पानी लाना पड़ता है । क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि इसका कोई इन्तजाम किया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, यह सूचना अब दी गई है इसको दिखवा लिया जाएगा ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, सालहावास की जो वाटर सप्लाई की स्कीम है उस स्कीम से कई गांवों को पानी दिया जाता है लेकिन वहां ट्यूबवैल्ज का पानी खराब हो गया है । नाहड को 'सी' वाटर सप्लाई स्कीम से पानी दिया जाताहै । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि सालहावास को 'सी' वाटर सप्लाई स्कीम से पानी दिया जाएगा क्योंकि सालहावास को जो पानी दिया जाता है वह खराब हो गया है?

श्रीमती शारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने सूचना दी है । हरियाणा के यूक–एक गांव की सूचना तो मेरे पास नही है ।

Mr. Speaker : Sufficient number of supplementaries have been put on this question please.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, भिवानी और महेन्द्रगढ़ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस हैं और यहां पर बहूत से गांवों मैं खारा पानी है क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी?

श्रीमती शारदा रानीः स्पीकर साहब, भिवानी में 257 गांवों और महेन्द्रगढ़ में 142 गांवों को पानी दिया गया है । इन डिस्ट्रिक्ट्स में समस्या सब से ज्यादा खराब थी और इसीलिए यहां सब से ज्यादा गांवों को पानी दिया गया है ।

श्री रामधारी गौडः क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि गोहाना तहसील में जो पांच–छः स्कीमें बनी हैं वे किस स्टेज पर हैं और वे कब तक पूरी हो जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, इंडिविज्वल स्कीम के बारे में मुझे पता नहीं है ।

Mr. Speaker : Yes, the Question Hour is over.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Wine and Beer Bars owned by the Government

***1616. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the number of Wine and Beer Bars together with their locations owned by the Government in the State as on 31st March, 1976, and

(b) the amount of profit accrued to Government from Wine and Beer Bars as referred to in part (a) above during the financial years 1974-75 and 1975-76, separately ?

परिवहन मन्त्री (के० एल० पोसवाल) :

(क) 31—3—76 को पर्यटन विभाग हरियाणा के अधीन कोई भी शराब व बियर बार नहीं थी ।

(ख) वर्ष 1974—75 में 31—8—74 तक 12 शराब व 5 बियर बार पर्यटन विभाग, हरियाणा के अधीन थीं जो कि 1—9—74 को हरियाणा पर्यटन निगम के बनने पर निगम को स्थानांतरित कर दी गई ।

शराब व बियर बार पर्यटक केन्द्र का एक अविभाजित अंग है और इन पर किए गए खर्चे का लेखा अलग से न रखे जाने के कारण वर्ष 1974—75 (31—8—74 तक) में इन द्वारा जो लाभ हुआ वह निकाला नहीं जा सका, इसलिए बार द्वारा हुए लाभ के बारे सूचना देना संभव नहीं है । 1—9—74 से सभी शराब व

बियर बारे' हरियाणा पर्यटन निगम की स्थानांतरित कर दी गई और अब यह निगम द्वारा चलाई जा रही हैं ।

Breweries and Distilleries owned by the Government

***1617. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number and names of Breweries and Distilleries together with their locations owned by the Government as on 31st March, 1976 ;

(b) the total amount spent on the construction of Breweries and Distilleries as referred to in part (a) above including machinery etc ; and

(c) the amount of income accrued to the State Government from the breweries and distilleries as referred to in part (a) above during the financial year 1974-75 and 1975-76, separately?

उद्योग मन्त्री (श्री हरपाल सिंह):

(क) सार्वजनिक क्षेत्र में एक में है जिसमें 51 प्रतिशत हिस्से हरियाणा स्टेट इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमेंट कारपोरेशन के हैं ।

(ख) 2.05 करोड़ रुपये

(ग) 1974—75 — 5.35 लाख रुपये

1975—76 — 9. 95 लाख रुपये

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

H.C.S. Officers

520 Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of H.C.S. (Executive Branch) Officers in the State as at present ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : इस समय (दिनांक 31– 5– 1978 को) हरियाणा राज्य में कुल 138 एच० सी० एस० (कार्याकारी शाखा) अधिकारी हैं । इन 138 अधिकारियों में से 6 अधिकारी राज्यसे बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

I.P.S. Officers

521 Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of I.P.S. Officers in the State as at present ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : 34, 1–7– 76 को

Reformatory steps for the Welfare of Prisoners

522. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Transport be pleased to state the reformatory steps taken by the Government for the welfare of prisoners in the Jails of Haryana from 1970-71 to 1975-76 ?

परिवहन मन्त्री (श्री के० एल० पोसवाल): अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में सदन के पटलपर रख दी गई है ।

विवर्णिका

बन्दियों की भलाई के लिए जो कदम उठाए गए

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के कल्याण के लिये वर्ष 1970–7 1 से लं कर 1975–76 तक सरकार द्वारा जो पग उठाये गए हैं वह इस प्रकार हैं :––

1970–71	रोहतक में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया मेल भवन बनाया गया।
1971–72	बच्चा जेल हिसार में एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति हुई।
1972–73	बन्दियों के मनोरंजन के लिए रोहतक में एक टैलिविजन लगवाया गया ।
1973–74	शून्य ।
1974–75	करनाल एवं गुडगावां जिला जेलों में टैलीविजन सैट लगवाए गए ।
1975–76	बच्चा एवं महिला बन्दियों के लिए हिसार में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए जेल भवन का निर्माण हुआ ।

जिला स्तर पर बोर्ड स्यापित किये गये जिस का काम आजीबन कारावास के बन्दियों के समय पूर्व रिहाई हेतू विचार करना ।

Hours Fixed for work in each Factory of Jails in the State

523. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Transport be pleased to state the number of hours fixed for work in each factory of Jails in the State of Haryana and the rate of remuneration paid to the prisoners for their work during the financial years from 1973-74 to 1975-76, separately ?

परिवहन मन्त्री (श्री के० एल० पोसवाल) :

(क) बंदियों के लेबर के कार्य का समय इस प्रकार है –

(1) व्यस्कों के लिये –प्रतिदिन 9 घंटों तक

(2) बच्चों तथा स्त्रियों के लिये :– प्रतिदिन 6 घंटों तक ।

(ख) बन्दियों को काम के लिये किसी किस्म का मेहनताना नहीं दिया जाता । तथापि कुछ विशष स्थितियों में अल्प राशि उपदान (पुरस्कार) के रूप में दी जाती है । '

कार्य–मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker : I present the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

"The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 8th and 9th July,

1976, be transacted as follows :-

Thursday, the 8th July, 1976 at 2.00 P.M.

1. Questions Hour.

2. Report of the Business Advisory Committee.

3. Non-Official Business.

Friday, the 9th July, 1976 at 9.30 A.M.

1. Questions Hour.

2. Motion under rule 15 regarding non-stop sitting of the House.

3. Motion under rule 16 regarding adjournment of the **House** Sine-die.

4. Papers to be laid on the Table.

5. Presentation of three Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extention of time for making the final Reports thereon.

6. Presentation of Tenth Report of the Public Accounts Com, mittee.

7. Legislative Business.

(1) The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1976 in respect of the Supplementary Estimates (First Instalment) 1976-77.

(2) The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1976 (alongwith notice of resolution for the

disapproval of the Ordinance by Ch. Ram Lal, M.L.A.).

(3) The Punjab Co-operative Societies (Haryana Second
Amendment) Bill, 1976. (alongwith notices of resolution for disapproval of the Ordinance by Ch. Shiv Ram Verma and Ch. Ram Lal, M.L.As.).

(4) The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 1976.

(5) The Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 1976.

(6) The Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill, 1976.

(7) The Haryana Race-Courses Licensing Bill, 1976.

(8) The Punjab Bhoodan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1976.

(9) The Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, 1976.

(10) The Haryana Veterinary Council Bill, 1976."

Home Minister (Shri K.L. Poswal) : Sir I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this. House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

गैर–सरकारी संकल्प

सतलुज–यमुना लिंक नहर को मुकम्मल करने संबंधी

Mr. Speaker : Shri Gulab Singh Jain to please move his Resolution.

Shri Gulab Singh Jain : Sir, I do not want to move the Resolution..

Shri K.L. Poswal : The other hon. Members who have given notice of the remaining two Resolutions on the Agenda for today, are not in the House.

Mr. Speaker : That means no resolution. There is no other business. A copy of one Resolution is with me and the Minister concerned has written that he has no objection for taking up this Resolution at a short notice. If the House agrees, **I** will allow it to be discussed at short notice, and we can discuss it today. The resolution is this-

"That this House recommends to the State Government to take immediate action to complete Sutlej-Yamuna Link Canal and take all necessary steps by June, 1977, so that it can utilise the Haryana's share of Sutlej Beas waters on completion of Beas-Sutlej Link Project by June, 1977, meet the demand for irrigation of arid and drought prone areas in the State and increase the present inadequate water allowance to the farmers."

Voices : Agreed.

Mr. Speaker : The Hon. Member Chaudhri Mehar Chand may move his Resolution.

Chaudhri Mehar Chand (Badopal) : Mr. Speaker, I beg to move—

That this House recommends to the State Government to take immediate action to complete Sutlej-Yamuna Link Canal and take all necessary steps by June, 1977, so that it can utilise the Haryana's share of Sutlej-Beas waters on completion of Beas-Sutlej Link Project by June, 1977, meet the demand for irrig ttion of arid and drought prone areas in the State and increase the present inadequate water allowance to the farmers.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House recommends to the State Government to take immediate action to complete Sutlej-Yamuna Link Canal and take all necessary steps by June, 1977, so that it can utilise the Haryana's share of SutlejBeas waters on completion of Beas-Sutlej Link Project by June,

1977, meet the demand for irrigation of arid and drought prone areas in the State and increase the present inadequate water allowance to the farmers.

चौधरी मेहर चन्द (बडोपल) : स्पीकर साहब, यह जो लिंक है, यह हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है । मेरी ख्वाहिश है कि इस बहस में चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का एम०एल०ए ० हो, उसको इस में हिस्सा लेना चाहिए । अगर हमने हरियाणा को सरसब्ज देख ना है, तो हमें गर्वनमैंट आफ इण्डिया कोइस बारे में प्रैस करना होगा कि इस लिंक को जल्दी से जल्दी बनाया जाए । तो इस से अच्छी चीज और कोई नहींहो सकती । स्पीकर साहब, इस वक्त हमारे पास वैस्टर्न यमुना कैनाल का, भाखडा कैनाल सिस्टम वगैरह का 1 मिलियन एकड़ फीट के लगभग पानी है । इसके मायने यह हुए कि यह 1 मिलियनएकड फीट पानी लगभग जो 45 लाख एकड़ एरिया के लिए काफी होगा इससे फालतू एरिया और इरिगेट नहींहो. सकता । (इस समय सभापतियों की सूची में सेएक सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, कारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा, हमारे डिफैंस मिनिस्टर साहब और हमारे मौजूदा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक खास बात की है, उन्होंने जो कोक्षिश की हैय हम उनकी इस कोशिश का एहतराम करते हैं । उनकी कोशिश में हमें 3.7 मिलियन एकड़ फीट पानी और मिलेगा । इसके मायने यह हुए कि जो पानी व्यास और रावी का मिलेगा, वह 1 7— 18 लाख एकड मिलियन भूमि केलिए काफी होगा । इसके

अलावा हरियाणा के अन्दर डायरैक्ट टयूबवैल्ज के जरिए भी इरीगेशन होगी । चेयरमैन साहब, प्राइवेट टबूब– वैल्ज के जरिए भी इरीगेशन होगी । इन दोनों सोरसिज से तकरीबन 12 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इस सारी पोजीशन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रावी व्यास का पानी पहुंचने से हरियाणा के अन्दर खुशहाली होगी और इससे कोई लगभग 75 लाख एकड़ भूमि को इरीगेट किया जा सकेगा । चेयरमैन साहब, हरियाणा का कल्चरेबल एरिया जो है, वह तकरीबन 90, 95 लाख एकड़ का है । मैं यह समझता हूं कि रावी व्यास का पानी आने के बाद केवल 15 लाख एकड़ भूमि ऐसी रह जाएगी, जिसमें पानी की दिक्कत होगी । लेकिन मैं अपनी हरियाणा सरकार से इस बारे में एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, अव्वल तो शायद हमारी हरियाणा सरकार इस ओर कोई स्टैप उठा ही रही है, अगर अभी तक कोई स्टैप– नही उठाया गया, तो कम से कम उस एरिया को (र–क पानी. जरूर मुहैया किया जाए । ऐसाहोने से हरियाणा की खुशहाली बढ़ेगी औरफिर कौन ऐसा आदमी होगा जो यह न चाहेगा कि मैं हरियाणा में न रहूं । चेयरमैन साहब, हरियाणा एक गुलशन होगा, ए वन स्टेट होगी । फिर मैं उस हरियाणा स्टेट के लिए हरी–भरी जगह की गुलशन शब्द इस्तेमाल करुंगा । तो मैं फिर अपनी सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि उस 15 लाख एकड़ भूमि के लिए एक पानी का अवश्य ही इन्तजाम किया जाए । चेयरमैन साहब, मैं एक बात कहूंगा कि रावी और व्यास का पानी लेने का हमारा इरादा क्यों है? इसकेलिए मैं एक शेयर कहूंगा ।

यह शेखर कोई बाराड नही है, मेरा अपना है । वह शेयर इस प्रकार है :

15.00 बजे

हम वीरानों में बहार लाकर ही दम लेगे,

बे हाल है, जो उन्हें खुशहाल बनाकर ही दम लेंगे ।

तो यह मेरा इरादा है और बीस सूत्रीय प्रोग्राम का भी यही इरादा है, जिसको हम पूरा करके रहेंगे, इसके लिए हम आखिरी बाजी तक लगा देगे । इसके अलावा हमें यह बात पक्की मान कर चलना पड़ेगा कि हरियाणा की खुशहाली का दारोमदार रावी व्यास का पानी है । अगर इसमें देरी हुई, तो मैं यह कहूंगा कि हमारे लिए यहां पर बतौर जनता के रिरैजैंटेटिव आने के कोई मायने ही नहीं रह जाते । अगर आप हरिजनों की भलाई का, बैकवर्ड क्लासिज की भलाई का या गरीब लोगों की भलाई का दम भरते हैं, तो इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाना होगा । (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई') । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे चेयरमैन के लिए कई वर्ड यूज करने पडते है क्योंकि कभी तो यहां पर स्पीकर साहब विराजमान होते हैं कभी चेयरमैन साहब और कभी आप । मैं सरकार सेएक बात जरूर कहूंगा कि उसने एक बात तो अच्छी कर दी है कि उसने आखिर अपने पानी का हिस्सा तो ले लिया । अभी तक वह पानी मिला नहीं है, इसके लिए तो वह काबिले माफी हैं, क्योंकि हमारा बड़ा भाई कहता था

कि हम 9 लाख एकड के लिए ही पानी देंगे, बाकी नही देगे लेकिन मैं दाद देता हूँ और अपना सिर झुकाता हूं उस प्राइम मिनिस्टर साहिबा के सामने, उस डिफैंस मिनिस्टर के सामने जिन्होंने इस मामले में हमारी सहायता की । यह हमारी खुशकिस्मती है कि हरियाणा का एक सबूत इण्डिया का डिफैस मिनिस्टर बना और उसकी उस मिनिस्टरी मे इतनी से हुई । उसने अपनी सारी ताकत लगा कर हमें 3.5 मिलियन एकड़ फीट हमारा हिस्सा पानी का दिलवाया । हमें यह और भी खुशी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह क्लैरिफिकेशन दी है कि वह हिस्सा 3. 73 मिलियन एकड़ फीट होगा । इस काम में चाहे देरी लगी, लेकिन मैं फिर भी उनको दाद देता हूं । इसके साथसाथ एक बात मत भूलिए कि हमें पंजाब से भी यह दरख्वास्त करनी है कि वह शीघ्र हमारा पानी दे, लेकिन वहा दरडवासत को रद्दी की टोकरी में फैक दिया जाताहै । तो इस काम को करने के लिए हमारे अन्दर हिम्मत होनी चाहिए । उनकी तो यह नियत है कि यह लिंक देरी से बने और पानी हरियाणा तक न पहुंचे । लेकिन हम ऐसा होने नही देंगे । इसके बाद मैं इरीगेशन मिनिस्टर को और कैबिनट को भी दाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके सैन्टर से अपना हिस्सा लेने में बहादुरो दिखाई और हरियाणा में उस काम को शुरु करदिया है, लेकिन हरियाणा में ही यह काम शुरु करने से बात नहीं बनेगी, बात तो तब बनेगी, जब हम पंजाब से यह कहे, उनको प्रैस करें कि वह हमारे प्रति सिम्पेथैटिक एटिच्यूड अडॉप्ट करें और हमें उस चौनल को बनाने दें । वह चौनल अगर बन गई, यह

बाजी अगर हमने जीत ली, तो आने वाली नसलें आपको याद करेंगीं । वह कहेगीं कि हरियाणा के अन्दर चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर हुए, गुप्ता साहब चीफ मिनिस्टर हु ए और एक शानदार कौबनट भी बनी, जिन्होंने इ तने शानदार काम किए । मैंने इस कैबिनट को आज तक शानदार नहीं कहा था, बल्कि अब तक मैं मुख्य मन्त्री को ही दाद देता रहा हूं । आज पहली बार हाउस में यह बात कहता हूं कि हमारी कैबिनट भी बहुत शानदार है, क्योंकि आज हमारे दिल के अन्दर एक बात पैदा हुई है । अगर यह बात पैदा न हुई होती, तो आज हरियाणा के अन्दर इस चौनल पर काम शुरु न होता । परसों हमने इसके लिए सप्लीमैंट्री के जरिए करोड़ों रुपया दिया है । तो अब मैं सरकार से कहता हूं कि वह पंजाब वालों से बात करें । मै भी बड़ी नम्रता के लफ्ज उनको कहता हूं क्योंकि मैंने देख लिया है कि हर काम नम्रता सेही होता है, सख्ती से नही होता । यह मेरा अपना तजरुबा है । क्योंकि पहरने मैं किसी वजीर के पास जब किसी काम के लिए जाता था तो यह कह दिया करता था कि अगर यह काम करना है तो कर दो नहीं करना न सही । तो वह काम साला होता नहीं था । अब जब से मैं हजूर कहने लगा हूं तो काम हो जाता है । तो इसी तरह से पंजाब वालों को भी मैं नम्रता से कह रहा हूं शायद वे मान जाए और रुकावट न डालें । इसके अलावा मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी प्रार्थना करुंगा कि वे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को रोज कुछ न कुछ कहते रहें, कि लानी जी मान जाओ, जल्द इस काम को कर. दो देर न करो । हमारे चीफ

मिनिस्टर साहब इस मामले में प्राइम मिनिस्टर की मदद ले सकते हैं, डिफैस मिनिस्टर की मदद भी ले सकते हैं । अगर इन्सान में हिम्मत हो तो सब कुछ हो सकता है और मैं कहता हूं कि वह हिम्मत हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में है क्योंकि पहले हमें 9 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये पानी मिलना था और अब इनकी हिम्मत से 37 लाख एकड़ के लिये मिलने वाला है । तो भलाई के कामों पर पानी नही फेरना चाहिये बल्कि उसकी दाद देनी चाहिये । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मार्फत चीफ–मिनिस्टर साहब से और कैबिनिट से यह दर्खास्त करुंगा कि इस मामले में अगर कोई डिले हो तो उसे फौरन चौक–अप करलें । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यह बात कही थी कि इस रैजोल्यूशन की हिमायत के लिये इसको जितना ही दोहराया जाए उतना ही कम है । वैसे बोलने के लिये तो इस पर आधा घंटा, पौन घंटा और भी गुजारा जा सकता है ।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बात यह कही कि 2 सीजनों के अन्दर अन्दर हरियाणा की सर जमीन को पानी मिल जायेगा लेकिन यह मिलेगा तब अगर हम सब चीफ मिनिस्टर को सहयोग देंगे, उसकी कैबिनिट को मजबूत करें और हम उनको विश्वास दिलाएं कि हम सब आप के साथ हैं, जिस तरफ आप बहायेंगे उसी तरफ बह जायेंगे । इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बात और भी इसी सैशन में कही थी कि आपके इलाके को भी पानी दे देंगे लेकिन मैंने कहा था कि भाखडा में से

आपने पानी तो दे दिया पर वाटर अलाऊंस कम है । अगर आप का वाटर अलाउस इन्क्रीज हो जायेगा फिर पानी मिल सकेगा । एशोयर्ड इरिगेशन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, तभी होगी जब सतलुज और व्यास का पानी हरियाणा की सर–जमीन पर बिछा देंगे वरना एशोयर्ड इरिगेशन एक ख्वाब ही रह जायेगा । मैं इस वक्त एशोयर्ड इरिगेशन पर इतना नहीं कहता जितना कि मुझे कहना चाहिए । इसको हम उस रोज से लेंगे जिस रोज से रावी व्यास का पानी आ जाएगा लेकिन आज मैं इसके बारे में कहने के लिए तैयार नहीं क्योंकि मेरा दिल मानता है कि 100 प्रतिशत एशोयर्ड इरिगेशन आज नहीं हो सकती क्योंकि कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया । पंजाब की, कुदरत ने मदद की है । हमारी जमीन का पानी स्वीट नहीं है, हम पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकते वहां वाटर टेबल नजदीक है और पानी स्वीट है । हम तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, दो बूंद पानी के लिए आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि कहीं बारिश बरसे और हमारी फसल सूखने से बच जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त नहरों के पानी की यह हालत है कि जिस वक्त फसल पकने पर आती है तो पानी नही मिल पाता और हमें नहर के कर्मचारी कई कई चक्कर कटवाते हैं । मैं एस० ई० और एक्स० ई० एन० को तो ब्लेम नहीं करता लेकिन एस० डी० ओ० और नीचे के लैवल वाले चक्कर कटवाते हैं । वे सोचते हैं कि परमात्मा हमारे हाथ में है । एशयोर्ड इरिगेशन के ख्वाब भी पूरे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्री– कल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढेगी और आज के एस्टीमेट्स से बहुत

ज्यादा प्रोडक्शन बढ जायेगी । कई भाई कम्पैरिजन किया करते हैं कि फलां ईयर में इतनी थी फलां ईयर में इतनी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा के भाइयों को दाद देनी चाहिए कि बगैर बारिश के भी प्रोडक्शन हम बहुत काफी करते हैं क्योंकि पानी के साधन मुहैया हुए हैं, ठीक है ट्यूबबैल्ज का भी बहुत फायदा हुआ है । कई भाई कह देते हैं कि यह बिजली बोर्ड की तारीफ इसलिए करता है क्योकि उसका मैंबर रहा है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बिजली बोर्ड गलती करता है तो मैं उसको भी माफ नहीं करता लेकिन बिजली बोर्ड ने प्रोडक्शन बढ़ाने में प्राइवेट ट्युबवैल्ज को कनैक्शन देकर बहुत कंट्रीब्यूशन की । पानी आने के बाद हरियाणा में खुशहाली आयेगी, तजारत भी बढ़ेगी, व्यापारी का व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारी को फायदा भीं होगा और जो छोटे किसान हैं वे भी खुशहाल होंगें और गुरबत हटेगी । हम कई दफा यहां कहा करते हैं कि बेरोजगारी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पानी आने के बाद बेरोजगारी भी दूर होगी । इस वक्त पानी तो है नही, इसलिए किसान क्या करे, उसने ऐसी हालात में ताश ही खेलनी है और क्या करेगा । जमीन में किसान तब काम करेगा जब पानी के साधन होंगे । एक बात मैं चीफ मिनिस्टर साहब से खासतौर से अर्ज करूंगा कि अगर इस काम. में पंजाब गवर्नमैंट की तरफ से डिले होती है तो आपको मिन्नत से भी काम लेना पड़े तो आप लें और अगर दूसरे हरबे इस्तेमाल करने पड़े तो वे भी करें लेकिन इसमें डिले नहीं होनी चाहिए ।

आखिर में डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक शेयर में हरियाणा के सपूतों से एक ही बात. कहूंगा––

ऐ शुजाओ ऐ दलेरो ए जवानों, ऐ वतन की आबरू के पासबानों,

तामीरे नौ में दिल लगाओ तस्वीरें नौ बनाओ गर कुछ मिटाना है तो गुरबत को मिटाओ ।

बस मैं इतना अर्ज करके आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

चौधरी रिजक राम (राई) : डिप्टी स्पीकर साहिबा चौधरी मेहर चन्द ने यह रेजोल्यूशन सदन के सामने रखकर हरियाणा की जनता पर बड़ा भारी एहसान किया । यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे हरियाणा के लोगों की जिन्दगी और खुशहाली वा–बस्ता है । इन्होंने इस तरफ न सिर्फ हरियाणा सरकार की और केन्द्रीय सरकार की बल्कि सारे देश के लोगों की तवज्जुह दिल गयीहै । इसमें कोई सन्देह नहीं हैकि रावी व्यास का पानी जो हरियाणा को मिलेगा उससे हरियाााणा की खुशहाली बढ़ेगी लेकिन इस बात पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । मैं रैकोल्यूशन के स्कोप्प पर ही बोलूंगा । इसमें नहर के बारे में जिक्र किया है । मैं उस पर ही अपने विचार रखना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि रावी ब्यास का पानी हरियाणा को मिलना है और यह इस नहर को जो लिंक कैनाल बननी है उसके बनाये जाने पर ही मिलेगा । यह

लिंक एक नहर ही. नहीं होगी और पानी लेने का एक साधन ही नही होगी बल्कि यह हरियाणा के लोगों के लिए या हरियाणा प्रान्त के लिए लाइफ लाइन होगी इससे आज हमें अगर हरियाणा की एक तस्वीर देखें जो बिल्कुल साफ है कि आज हरियाणा में पानी के बगैर लोगों को कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाईयां हैं तो इससे जाहिर होगा कि इस नहर की जल्दी से जल्दी बनने की कितनी आवश्यकता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा में कोई अपना दरिया नहीं है, कोई दरिया ऐसा नहीं, जो हरियाणा की भूमि में से गुजरता हो । एक घग्घर का करिया है, वह भी फ्लशी है । बरसात में पानी आ जाता है और बरसात खत्म होते ही पानी खत्म हो जाता है । जो बारानी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, उनको जहां यह दरिया पानी की सुविधा देता है, कुछ पीने के पानी में मदद देता है, कुछ आबपाशी हो जाए इसमें सहायता देता है, वहाँ तबाही भी मचाता है, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन इसके अलावा कोई दारिया नहीं । दरिया जमूना इधर है । उसके बारे में क्या जिक्र करूं ।

हम देखते हैं हिसार जिला जिसमें भाखडा का पानी जाता है, महेन्द्रगढ़ भिवानी और गुड़गांव जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी ऐसा साधन नही जिससे वहां आबपाशी हो सके, किसान अपने खेतों को पानी दे सके । वही आज से नही, बहुत पहले से बल्कि जिस समय मेरे पास सिचाई विभाग का कार्यक्रम था, हमने अपने जितने भी प्रोजैक्ट आफिसर्ज थे, इरीगेशन रिसर्च आफिसर्ज थे,

डायरैक्टर्ज थे उन सब के जरिए एक सर्वे कराया था । सबसे मुश्किल की बात उस इलाके में यह है कि वहाँ अन्डर ग्राउन्ड वाटर नहीं है । इधर अम्बाला जिला है इसमें बहुत से छोटे छोटे दरिया गुजरते हैं जो तबाही मचाते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिब । आपको मालूम है कि यहां जो पहाड़ी इलाका है या मैदानी इलाका है, जगाधरी और जमुनानगर के इलाके को छोड कर, जैसे टांगरी मारकंडा आदि, वहां पीने के पानी की कमी है । यहां जो जमीन का लेयर है वह ऐसा हैकि उसके अन्दर पानी नहीं जाता और जो दरिया गुजरते हैं वे तबाही मचाने के अलावा न आबपाशी मे मदद देते हैं न पीने के पानी में मदद देते हैं । इस तरह से कितना भारी इलाका, गुडूगांव, महेन्द्रगढ, भिवानी और हिसार जिलों का ऐसा है जिनमें न तो पानी आबपाशी के लिए है और न पीने के लिए है । इसी तरह से कितने ही देहात अम्बाला जिले के आज एक स्टेटमैंट में बताए गए जिनमें पीने के पानी की कमी है, जहां लोग पानी के लिए तरसते हैं । फिर हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भाखडा कैनाल से आबपाशी होती है या वैस्टर्न जमुना कैनाल से आबपाशी होती है । जहां तक वैस्टर्न जमुना कैनाल का ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको मालूम है कि इस दरिया में हमारा और यू ० पी० का हिस्सा है । कुछ पानी दिल्ली को देते है । बरसात के मौसम में इस में शैलाब आकर के तबाही होती है और जिस वक्त आबपाशी के लिए जरूरत होती है, नवम्बर से जून तक, डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत ही अच्छा मौसम हो तो मैं नही कहता, वरना केवल दो हजार क्यूसिक्स पानी ही दरिया में

रहता है । हांसी ब्रांच, दिल्ली ब्रांच और जुई कैनाल इन तीनों की रिक्वायरमैंट जहां बारह हजार से चौदह हजार क्युसिक्स तक है वहां इसमें केवल दो हजार क्यूसिक्स पानी रह जाता है और उसमें सेऐ बजौरप्शन लौसिज हैं, आपरेशन लौसिज हैं तीन सौ क्यूसिक्स के करीब, फिर दिल्ली को पानी देते हैं । यह सारी कटौती करके बड़ी मुश्किल से नवम्बर से दिसम्बर जून तक कोई हजार क्यूसिक्स या आठ सौ क्यूसिक्स पानी हमे मिलता है । इसका नतीजा यह होता छैं कि हांसी ब्रांच और दिल्ली ब्रांच रोटेशन में चलानी पडती है और उनसे मिलते हुए रजबाहे और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बारी बारी चलानी पड़ती हैं । मंहगे से मंहगा बीज लेकर किसान गेहूं की और दूसरी फसलें बोता है लेकिन उसको एक पानी मिलने के बाद शायद सारे सीजन में दूसरी बारी नही मिलती । इसी तरह की हालत भाखडा कैनाल सिस्टम पर है जहां इटैनसिटी तो काफी है मगर सैडी एरिया इतना है कि उस इंटैनसिटी से काम नही चलता । ऐसा एरिया हमारे पास है जहां अन्डर ग्राउन्ड वाटर नहीं है, दरिया का पानी कम है, नहरों का पानी कम है । ऐ से हालात में यहां के किसान को तो हमें बधाई देनी चाहिए कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वह हरियाणा में पैदावार बड़ाने में काफी कामयाब हुआ है । सरकार ने भी जो सहायता की है उसको भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते, मगर जो मुश्किलात हमारें सामने है उन सबको हल कराने में हम सबको तवज्जुह देनी चाहिए ताकि किसी तरह से हरियाणा के इलाके में पानी फालतू मिले और जल्दी से जल्दी खुशहाली बडे । अब मुश्किल क्या है? डिप्टी

स्पीकर साहिबा, इस चौनल के बारे में, रावी ब्यास के पानी के बारे मे जितना सोचा जाहू या जिक्र किया जाए उतना ही दुःख होता है कि इस देश में हो क्या रहा है । आखिर यह एक ही राष्ट्र है । हरियाणा या पंजाब कोई दूसरे देश नहीं, कोई दुश्मन देश नहीं । हरियाणा बनने से बहुत पहले, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बहुत ही सूझ–बूझ और बहुत आगे के भविष्य का ख्याल रखते हुए, इंडस वाटर ट्रीटी करके रावी–ब्यास का पानी हरियाणा और पंजाब के इलाके के लिए हासिल किया । उस वक्त से, आपको मालूम है, मार्च सन् 1970 से रुपया देने के बाद रावी व्यास का जितना पानी पाकिस्तान लेता था वह सारे का सारा हरियाणा और पंजाब को मिल चुका है । होना तो बहु चाहिए था कि मार्च 1970 से पहले यह चौनल बनाकर, सारा हिस्सा तय करके, पानी मिल जाना चाहिए था । मार्च 1 970 में पाकिस्तान ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, उन्होंने पानी लेना बंद कर दिया, 6 साल आज हो चुके है, लेकिन अफसोस है कि आज भी वह पानी जाया जा रहा है । वह किसान जिसकी भूमि पानी के बगैर तरसती है, वह हरियाणा जिसको पीने के पानी की मुश्किल है, जिसके इलाके में मवेशी और मनुष्य एक ही जोहडू में पानी पीते हैं वह आज भी पानी के एक एक कतरे के लिए तरसता है लेकिन दूसरी तरफ कितना भारी पानी 6– 7 साल से जाया जा रहा है । हम उसका केन्द्रीय सरकार से फैसला नहीं करा सके । उसका क्या कारण है क्या–क्या इफ्लूएंसिज काम करते रहे मैं उन बातों में मेंही जाता लेकिन हरेक आदमी महसूस कर रहा है कि सरकार को 8 साल

तक इस बात का फैसला कर देना चाहिए था ताकि हम इस डुलाके को पानी दे सकते । इससे ज्यादा अवगुण की बात कोई हो नहीं सकती । यह देश है जहां सब कुछ बरदाश्त हो सकता है । अगर कोई और देखा होता तो इतनी कोताही के बाद कोई बरदाश्त नहीं करता । शुक्र है आखिर इसका ऐसला हूआ और हरियाणा के गैर–माफिक नहीं हुआ, माफिक हुआ । इसकी सारी डिटेल में इम समय जाने की आवश्यकता नहीं लेकिन थोड़ा जिक्र कर दूं । इस नहर के बनने की और पानी को हासिल करने की अहमियत को हरेक हरियाणा का आदमी महसूस करता है । पहले भी सन 1964– 65 में इसके बारे में सरकार ने एक ऐक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी कि यह जो पानी 7 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा मिलेगा रावी–व्यास से इसकी किस तरह से तकसीम की जाए उस कमेटी के चेयरमैन कालकट साहब थे तथा बडे बड़े चीफ इंजीनियर और दूसरे बड़े लायक आदमी भी उसमें थे । उन्होंने सारे हालात को देख कर यह रिपोर्ट दी वो कि हरियाणा को 47 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए । उन्हौने कहा था कि यहां की भूमि को अधिक पानी की आवश्यकता है । 1964 में यह फैसला लिया था कि यह नहर जल्दी से जल्दी बनायी जाये और 1985 तक इस पानी को इस्तेमाल करना शुरु कर दिया जाये । केन्द्रीय– सरकार की तरफ से फैसला न होने की वजह से आज 1978 तक यह पानी प्रयोग में नहीं आ सका यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि 55 करोड़ रुपया देकर इस पानी को पाकिस्तान से हासिल किया गया था । यह नहर न बनने की वजह

से हरियाणा को बहुत नुक्सान होता रहा । कोई भी आदमी इस प्रान्त का नहीं हो सकता जिसको इसके न बनने से दुःख न हूआ हो । आज चाहे यह केन्द्रीय सरकार की मेहरबानी से, चाहे प्रधान मन्त्री महोदया की मेहरबानी से, चाहे मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास गुप्त की या चौधरी बंसी लाल की मेहरबानी से यह फैसला हुआ । मैंने तो पिछले सैशन में कहा था कि जहां इन दरियाओं के पानी के हिस्से का सवाल है इस का विभाजन जल्दी से जल्दी होना चाहिए । आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे में से एक प्रभावशाली सदल जो यहां पहले मुख्य मन्त्री थे वे केन्द्रीय सरकार में हैं । उनकी वसासत से हम इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करा सकते हैं । वैसे जो हमें पानी का हिस्सा मिला वह एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक नही मिला लेकिन मुझे यह खुशी है कि फैसला तो हुआ । पंजाब के लोगों की जिद्द को देखते हुए तो ऐसा मालूम देता था कि हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है । वे तो कहते थे कि री–आर्गे– नाइजेशन एक्ट के तहत हरियाणा का इसमें कोई हिस्सा नहीं है । वे तो इसको अपनी प्रोपर्टी समझते थे । पंजाब का एलान था कि हरियाणा इसमें हिस्सा नहीं मांग सकता । उन सारी बातों को दरगुजर करके हरियाणा को अच्छा हिस्सा मिला और इसके लिए मैं दिल्ली की सरकार को या हरियाणा सरकार को धन्यवाद दिये बगैर नही रह सकता । अब सवाल तो यह है कि हरियाणा की भूमि में इस पानी को कैसे लाया जाये । दों–तीन दिन हुए हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि यह नहर 209 किलोमीटर बननी है । इसमें से तकरीबन

103 किलोमीटर हरियाणा के एरिया में बननी है और 108 किलो–मीटर नहर पंजाब के एरिया में बननी है । पंजाब के एरिया में नहर बनने में हमारे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि पंजाब के अपने इंजीनियर हैं लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ । जो नहर पंजाब के एरिया में बननी है उसका यह भी. फैसला नहीं हुआ है कि कौन सर्वे करेगा, उसकी एलाइनमैंट कौन करेगा, कौन खर्च करेगा, यह सब पंजाब के अख्तिया– रात में मालूम देता है । वे हरियाणा के इंजीनियर्ज और कर्मचारियों के हाथों में नही छोड़ेंगे, वे सारा काम अपने हाथ में रखेंगे क्योंकि इसमें उनकी अपनी दिलचस्पी है । वे तो चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा देर लगे । देर होने से उनको फायदा है । अब सब से पहला सवाल तो यह है कि हम जल्दी से जल्दी यह फैसला करायें कि सर्वे का काम, एस्टीमेट्स वगैरह लगाने का काम हरियाणा के कर्मचारियों और इंजीनियर्ज के हाथों में सौपा जाये । ऐसी बात नहीं है कि अभी तक देश में कभी ऐसी बात हुई ही न हो । पहले ऐसा हुआ है । जिस वक्त सन् 1984 में दिल्ली में फल्ड आया, नजफगढ दिल्ली के पास है वहां ड्रेग लाइन बननी थी । दिल्ली के पास इतने इंजीनियर्ज थे, एडमिनिस्टेरशन के कर्मचारी थे लेकिन फिर भी यह काम उन्हेंने पंजाब सरकार के जिम्मे सौंपा । पंजाब सरकार ने यह ड्रैग लाइन बनायी। इसी प्रकार से एम० आई० टी० सी ० हरियाणा ने बिहार के अन्दर ट्यूबवैल्ज लगाये तो ऐसी बात नहीं है कि पंजाब कोई दूसरा मुल्क है, जिसमें हमारे अधिकारी काम नहीं कर सकते । आपस में हम भाई हैं, एक दूसरे के

पड़ोसी हैं, एक दूसरे से आपस में हमदर्दी रखते कुंए, इसलिए हमारे इंजीनियर्ज काम कर सकते हैं ।

अब अगला सवाल मेरा यह है कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? पंजाब की टैरेटरी मेंजो नहर बनेगी उसको कौन बनायेगा । यह सवाल भी हल होना चाहिए । अगर हम पंजाब के इंजिनियर्ज पर यह बात छोड़ दें तो इसमें रुकावट आ सकती है । मेरा मतलब यह नहीं हे कि मैं उनकी नीयत पर शुबहा करता हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इसलिए कहता हूं कि जितनी लग्न हमें इस काम को पूरा करने की हो सकती है उतनी लग्न पंजाब वालों को नही हो सकती । इसलिए सब से पहला काम यह है कि सर्वे का काम कराने के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए हमें दिल्ली की सरकार से या पंजाब के मुख्य मन्त्री जी. से बातचीत करके इस फैसले को जल्दी से जल्दी कराना चाहिए । एक डेट मुकर्रर कर लेनी चाहिए कि इस तारीख तक यह काम पूरा हो जाये । यह साराकाम हरियाणा के अफसरों और कर्मचारियों को करना चाहिये ताकि जल्दी से हो सके ।

तीसरी बात यह है कि सर्वे होने के बाद जमीन भी इक्वायर करनी है । जमीन इक्वायर करना उनके अपने हाथ में है । वे पंजाब लैन्ड एक्यूजिशन एक्ट के मुताबिक ही उसकी कीमते वगैरह फिक्स करेंगे । इन बातों में कितना समय लगता है ये सारे सवाल हैं जो हमें तय. करने हैं । अगर हम इस तरफ बहुत ज्यादा तव्वजोह दे कर इस काम को कराने की कोशिश न करेंगे तो मैं

यह महसूस करता हूं कि यह जो पानी का फैसला हुआ है इसका कोई लाभ हम लोगों को न होगा । मैं तो यह समझता हूं कि कितने सालों से वे हमें झूठे विश्वास दिलाते रहे हैं ।

मुझे कई इंजीनियर्ज से भी बात करने का मौका मिला है । डेढ़ साल पहले एक आर्टीकल ट्रिब्यून में छपा था । वह एक इंजीनियर ने लिखा था । उसने सारे फैक्टस एण्ड फिगर्ज लिखीं थीं, बड़ी दलील दे कर लिखा था कि अगर यह काम शुरू भी कर दिया गया तो इस नहर को बनाने में कम से कम 5– 8 साल का अर्सा लगेगा । छः साल तो उस वक्त लगेने जब हम दिन रात, राउन्ड दी क्लाक काम करेंगे । अगर हम अपने इंजीनियर लगा कर जमीन इक्वायर करने का काम कर लेते है और फार्मेलिटीज को पूरा करने में साल छः महीने गुजार दिये. तो हमारा हिस्सा जो मुकर्रर हुआ है उसको लेने में कई साल लग जायेगे । अब यह नहर बनाने का सवाल है । इस पर सारी ताकत सरकार की लगनी चाहिए । वैसे मैं पड़ोसी प्रान्त की सरकार के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता लेकिन जैसा कि पानी देने के मामले में रवैया पीछे रहा है बिजली देने का मामला सम्भव नहीं लगता कि हमें जल्दी से मिल जाये । पंजाब सरकार ने उन. सब बातों में जिद्द की है और अब भी हमें सन्देह है क्योंकि जो काम हम करना चाहते हैं, जो नहर हम बनाना चाहते है उसमें पंजाब सरकार हमारा सहयोग दे, ऐसा मैं नहीं मानता । मुझे तो पूरा सन्देह है । उसमें रुकावट आ सकती है । उन मुश्किलात को हल करने के

लिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता हैं । मै विरोधी दल की तरफ से सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में हम पूरा सहयोग देंगे । विरोधी पार्टी के सदस्य ही नहीं बल्कि हरियाणा का एक–एक बच्चा, स्त्री, पुरुष हरियाणा सरकार के साथ सहयोगी होगा । सरकार जो कदम उठाएगी, जो फैसला करेगी उसमें हरियाणा के एक–एक आदमी का सहयोग होगा । लेकिन मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस मामले में कमजोरी दिखाएगी या सरकार भाई बन्दी के नाते या लिहाजदारी के नाते कम दिलचस्पी लेगी या पूरी शक्ति से काम नहीं करेगी तो उसे याद रखना चाहिए कि हरियाणा की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी । सरकार आज जो सब्जबाग दिखा रही है कि हमने इतना पानी ले लिया, अगर वहइस काम में ढील देगे तो मेरे ख्याल में देहात में उनको काम करना और वहां जाना मुश्किल होगा । आज कहा जा रहा है कि जवाहर लाल नेहरू कैनाल पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है । हम दूसरी योजनाए बना रहे हैं और उन योजनाओं से यहां पानी देंगे वहां पानी देंगे । सवेरे ही मुख्य मस्ती महोदय बता रहे थे कि रिवाडी में पीने के पानी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम बनाने की जरूरत नहीं है हम जवाहर लाल नेहरू कैनाल से पानी दे देंगे । बड़ी अच्छी बात है कि कैनाल से पानी आप देंगे । यह तो वही कहावत हो गई कि गांव तो बसा नहीं और मंगते फिर गए । मैं एक कहावत बता देता हूं––दों भाई थे । उनके खेत गांव के बिल्कुल नजदीक थे । एक भाई ने कहा

कि हम ईख बोए' । दूसरे ने कहा कि ईख तो बो दें लेकिन गाँव वाले नुक्सान करेंगे । आखिर उन्होने फैसला किया कि गन्ना बोने से पहले हम गांव वालों का इन्तजाम करदें जिससे वे हमारा नुक्सान न करें । ऐसा सोचकर उन्होंने गांव में आग लगा दी । जब गांव वालों ने देखा कि आग लग रही है तो वे भागकर आए और आग बुझाने लगे । उन्होंने देखा कि दोनों भाई कह रहे हैं कि चूस लो गन्ने । गांव वालों ने सोचा कि यह मामला क्या है । कहीं यह बात न हो कि लोगों को दिलासा दे दो और पानी दस साल तक न दो । इसके लिए हरियाणा की जनता आपको माफ नहीं करेगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि हरियाणा और पंजाब का इस पानी का मामला तय होने से सारी बातों का फैसला नहीं हो जाएगा और भी कई मसले हैं जैसे बिजली का मामला है, थीन डैम का मामला है उनको भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए । सरकार को जिन नहरों को बनाना है, उनको प्रायरिटी बेसिज पर बनाना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही चौधरी मेहर चन्द को और सरकार को दुबारा यकीन दिलाना चाहता हूं कि वे इस मामले में दिल से, मेहनत से काम. करें और नहर को जल्दी बनाने की कोशिश करें, जो मसले आपस में हल करने हैं उनको जल्दी हल करें । हरियाणा की जनता उनके साथ है ।

श्री रामधारी गौड (गोहाना) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, जो प्रस्ताव मेरे लायक दोस्त चौधरी मेहरचन्द ने सदन में

रखा है, यह बहुत अहम प्रस्ताव हैऔर यह हरियाणा की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का निचोड़ है क्योंकि बहुत सालों से हरयिाणा की जनता, हरियाणा के लोग इस आशा में बैठे थे कि कब उनके खेतों में यह पानी मुहैया होगा । आप जानते हैं कि हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है, बहुत लायक है । वह 24 घन्टे में 18 घन्टे काम कर सकता है । यहां की जमीन भी बहुत उपजाऊ है । लेकिन एक ही कमी थी– कि पानी बहुत कम मिलता था । आप जानते हैं कि हरियाणा में कुछ जमीन को भाखडा का पानी मिलता है और कुछ जमीन को जमना मैया, जो एक मुकद्दस दरिया है, का पानी मिलता है लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो इसमें बाढ़ आती है और जब खुशहाली होती है और किसान को पानी की जरूरत होती है तो सूख जाता है । आप जानते हैं कि किसान बगैर पानी के क्या करे । जिस जमीन को छः पानी की जरूरत होती है उसको मुश्किल से एक पानी भिलसा है लेकिन फिर भी वह अपनी मेहनत से, कही टयूब– बैल लगाता है, कहीं ऊंचे खेत में पानी को डालो के जरिए ऊपर चढ़ाता है । किसान पानी का एक कतरा भी जाया नहीं जाने देता । हरियाणा के किसान की हिम्मत मजबूत है वह हिम्मत वारना है लेकिन उसकी अपनी मजबूरिया हैं । जब कभी रावी–व्यास के पानी का जिक्र आता है तो वह खुशी से झूम पड़ता है । जितने भाई यहां सदन में बैठे हैं जब वे देहातों में जाते हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं कि रावी–ब्यास का जो पानी मिलना है वह कब मिलेगा वह पपीहे की तरह पानी की आशा बान्धे बैठा है और आज हमें 3.

5 मिलियन एकड़ पानी मिला है । वैसे हरियाणा का क्लेम 4. 8 मिलियन एकड का था । लेकिन जो फैसला हो गया वह ठीक है । इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिऐ हमें कोशिश करनी चाहिए । जो पानी हमें मिलना है उसको जल्दी किसान के खेत तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करें । लिंक कैनाल जितनी जल्दी बन जाएगी उतनी ही जल्दी किसान के खेत में पानी पहुंच जाएगा । मेरे भाई ने एक हवाला दिया था कि ट्रिबयून में कोई खबर छपी थी कि इनको बनाने में पांच साल लग जाएंगे । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा के इन्जीनियर्ज बहुत मेहनती हैं । इन्होंने आगमेन्टेशन कैनाल एक साल के अन्दर बना दी । अगर जमीन ऐक्वायर करने का फैसला हो जाए तो यह काम हरियाणा के इन्जीनियर्ज को सौंप दिया जाए । मेरा ख्याल है कि डेढ़–दों साल के असें में यह काम मुक्कमल कर दिया जाएगा । मैं पंजाब के भाईयों की नीयत पर शक नही करता, वे हमारे पड़ौसी भाई हैं और हमारे दुख सुख से वाबस्ता हैं । आज पंजाब में कोई कमी पड़ती है तो उसका नुकसान हमें भी होता है । अगर हरियाणा में किसी बात की कमी पड़ती है तो उसका नुकसान पंजाब वालों को भी होता है । हमारा देश एक है, हम सब को एक ही देश के समझते हैं । यह जो प्रांतों की बौंडरिया बनाई गई हैं यह तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं । तो मैं यह समझता हूं कि अगर पंजाब के किसान को कोई तकलीफ होगी तो उससे हरियाणा के किसान को कोई खुशी नहीं होगी । हम सदा एक ही झण्डे के नीचे खड़े

होते हैं । सो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह पंजाब से जमीन एक्वायर करके जल्दी से जल्दी ही हमारे इंजीनयिर को दे दे । वे एक दम अपना काम शुरू करेगें और हमारे अन्दाजे से पहले ही काम को खत्म कर देगें, इस में कोई शक शुबाह की गुजायश नही है लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें कुछ कायदे कान्ऊन हैं । पर देश के सामने, देश की जरुरत के सामने, देश के उत्पादन के सामने वे कायदे कानून जो बहुत पुराने बनाये हुए हैं उनको तोड़ा मरोडा जा सकता है, उनको बाइ पास किया जा सकता है । ऐसे कामों पर वार–फुटिंग पर काम होना चाहिए । जिस तरह लड़ाई के दिनों में सभी कायदे कानूनों को तोड़कर सालों में होने वाले कामों को महीनों में किया जाता है, उसी तरह से इस चौनल के काम को करना चाहिए । इस के बनने से लोगों में खुशहाली आएगी, गरीबी दूर होगी क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने गरीबी को दूर करने के जो ख्वाब देखे है कि मुल्क में कोई गरीब न हो, कोई भूखा न रहे, हरेक आदमी को काम धन्धा मिले, वे पूरे हों और इसका एक ही जरिया है कि यह सतलुज व्यास लिंक कैनाल बहुत जल्द ही पूरी की जाए ताकि जो हमारे हिस्से का पानी है वह जमीदारों के खेतों में पहुंच सके और उस खेत ने जो मजदूर – खाली है जिसके पास कोई काम धन्धा नहीं है उसको काम मिल सके । ऐसा होने से वह खुशहाल हो सकेगा और अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से पाल पोस सकेगा । मैं समझता हूं कि खेती–बाड़ी जो है वह दे श की बैक बोन है । अगर किसान को पानी मिलेगा तो उससे खेती–बाडी अच्छी होगी और हरेक आदमी

को खाने को अनाज मिलेगा! दुकानदार का सामान बिकेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा ये सड़कें, पुल और हस्पताल वगैरह तभी अच्छे लगेंगे जबकि हरेक आदमी को खाने को अन्न मिलेगा और अगर अन्न नही मिलेगा तो देश में शांति नहीं हो सकती । मैं यह समझता हूं कि ला एण्ड आर्डर से बढ़कर अनाज की अधिक जड रत है और अनाज तभी पैदा हो सकता है जबकि किसान को पानी मिलेगा, खाद मिलेगी और अच्छे औजार मिले गे । अगर पानी की कमी होगी तो खाद जाया जा एगी, दूसरे साधन जाया जाएगे । इस बार तो वैसे ही किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है । बारिश भी कम हु ई है आप किस (न के दिल पर हाथ रखकर देखिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है । चण्डीगढ जैसे शहर में तो चहल पहल है पर आप गांवों में जाकर किसानों की हालत को दे खे' तो आप को पता चलेगा कि आज किसान कितना दुखी है । उसको चक्कर आ रहे हैं । अगर पहले ही यह लिंक चौनल बन जाती तो आज इतनी दिक्कत किसानों को न होती । डिप्टी स्पीकर साहिबा, केवल 50 परसेन्ट जमीन ऐसी है जो कि केवल बरसाती पानी पर निर्भर करती है । जहां बरसात नहीं होती वहां दाना नहीं उगता और पानी की कमी की वजह से फसल आधी ही पैदा होती है । आप के जरायत के महकमें वाले आंकड़े बताते हैं कि हमने एक एकड़ में फलां नम्बर का बाजरा पैदा किया है, फलां नम्बर का गेहूं पैदा किया है अगर पानी की कभी हो जाए तो यह आंकड़े कागजी ही रह जाते हैं । हम जब देहातो में जाकर पूछते हैं कि भाई बीज अच्छे थे फिर आपकी

पैदावार क्यों नहीं कुकी! पैदावार को बढ़ाओ. पंज वा लो की पैदावार आपसे ज्यादा है तो वे कहते हैं कि वे 10, 15 पानी देते हैं, अच्छी खाद इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे यहां तो कु छ भी नहीं है हम इतनी पैदावार कहां से करे । डिप्टी स्पीकर साहिबा! ये जो आंकडे लगाये जाते है ये उन लोगों के हैं जिनके पास अच्छे साधन हैं । हम यह आंकड़े उस वक्त लगाएं जब हमारे पास साधन हों । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै समझता हूं कि चा हे हम कितनी जद्दों जहद करें, कितनी मेहनत करें जब तक हमारें पास साधन नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते । इसके लिये हमें चा हि ये कि हम मिलकर गवर्नमेंट आफ इंडिया को यह कहे कि इस चीज का जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए । पंजाब के भाइयों को दु लाकर उन से हमें जमीन दिलवाई जाए, उसके बाद हम अपना नकशा बनाएगे ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम काम करना चाहते हैं । यह बात नहीं कि पंजाब के इजीनियर्ज ही काम करते हैं, हम नही कर सकते । कोई भी इंजीनियर काम करता है वे सभी एक देशे कें है, चंद साल पहले यह हरियाणा पंजाब का ही एक हिस्सा था अगर हमारे पास साधन होंगे तो हमारे इंजीनियर भी उन्हीं की तरह दिलोजान से काम करेंगे । मै तो यह कहूंगा कि चाहे सरकार अभी कोई स्कीम बन्द कर दे बेशक सड़कें न बनाए, टूरिजम का काम बन्द कर दे लेकिन इस कैनाल के लिये इस चौनल के लिये सबसे पहले पैसा दे । इस से यह फायदा होगा

कि हमें बिजली भी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्यूबवैल्ज भी चल सकेंगे और किसान की खेतीबाडी भी अच्छी हो सकेगी, अनाज खूब होगा, किसान खुशहाल होगाऔर हरियाणा में खुशहाली आएगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, 85 प्रतिशत लोग खेती– बाड़ी पर निर्भर करते है और जो 1 5 प्रतिशत हैं उनका भी एक पांव जमीन पर है और दूसरा पांव दस्तकारी पर है । उनको भी यह न समझे कि उनका कोई खेती–बाड़ी से ताल्लुक नहीं है । आप देखें कि जो बड़े बड़े दस्तकार हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस हैं उनके भी 5–7 किल्ले किसी गांव में आप पाएंगे । यह बात अलग है कि वह टैक्स को छिपाने के लिए ऐसा करते हों । पहले मैंने देखा है कि बडे–बडे इंडस्ट्रियलिस्टस गांवों में 20– 30 किल्लो के लिये फिरते थे । मैं दूसरी बात पर आ गया यह तो टैक्स वालों का काम है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं पानी के लिये कहता हूँ बेशक आपका अम्बाला का इलाका कैनाल का नही है, ट्यूबवैल्ज का है लेकिन ट्यूबवैल्ज भी तभी कामयाब होंगे जब तमाम हरियाणा में पानी होगा । नहरों में पानी कम होगा तो जमीन के पानी में कमी बढ्ती जाएगी । आपने देखा होगा कि जब फल्ड आते हैं तो आपके इलाके का वाटर लैवल ऊंचा आ जाता है, तो इन नहरों का और दरियाओं का ट्यूबवैलों से बहुत बड़ा संबंध है, नहरों में पानी की कमी होने से यह नही है कि हम ट्यूबवैलों से पानी ले लेंगे और नहरों से हमारा कोई सम्बन्ध नही रहेगा तो मैं समझता हूं कि हम जो एक आशा लगाए बैठे हैं उसके ऊपर चौधरी मेहर चन्द ने यह जो प्रस्ताव रखा है,

यह उनके दिल की आवाज है और इस प्रस्ताव को जब हरियाणा का किसान सुनेगा कि हरियाणा विधान सभा में यह प्रस्ताव पेश हुआ था और बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है और हमारे भेजे हुए नुमायंदे इसके लिये लड़ रहे हैं तो उनको भी खुशी होगी और हौसला होगा । तो मैं सारे सदन से आशा करूंगा कि वे जल्द से जल्द इस प्रस्ताव की भावना को अमली– जामा पहनाने के लिये, हर किस्म की जद्दोजहद के लिये तैयार हो जाएं । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करके बैठ जाता हूं ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : डिप्टी स्पीकर महोदया, चौधरी मेहर चन्द जी ने जो यह रैजोल्यूशन हाउस के सामने पेश किया है इस ने मुल्क के लोगों को दो हिस्सों में बांटा है । एक तो वे जो एमरजेंसी को वैलकम करते है और एक वे जो इसको अपोज करते हैं । चौधरी मेहर चन्द ने सैन्ट्रल गवर्नमैंट पर, हरियाणा गवर्नमैंट पर और पंजाब गवर्नमैंट पर और उन लोगों पर जो एमरजेंसी के हिमायती हैं एक क्वैश्चन पुट किया कि क्या यह एमर– जैसी नेशनल कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होनी है या महज हमारा प्रोपेगन्डा ही हे? अपोजीशन को अन्दर बैठा कर रख दिया । क्या मैं अपनी सैन्ट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्न– मैट से यह उम्मीद कर सकता हूं कि वे मुल्क की तारीख मैं यह नहीं लिखने देंगी कि जिस वक्त मुल्क में नेशनल एमरजैसी डिकलेयर थी, जिस वक्त गवर्नमैंट के पास स्पैशल पावर थी, उस वक्त सिविल लिबर्टीज को कुचल दिया गया और वे लोग जिन्होंने

नेशन को आजाद करवाने की शपथ ली थी, चरण सिंह और दूसरे बुजुर्ग, उन लोगों को अन्दर किया गया । वह ताकत क्या जो इन दो छोटी सी स्टेटस के एक छोटे से मसले पर दो साल लगने दे । एमरजैंसी में तो इतनी पावर होती है कि अगर किसी सूबे की गवर्नमैंट से किसी काम में दो मिनट की डिले हो जाए तो गवर्नर उस गवर्नमैंट को दो मिनट में सस्पैड कर सकता है । मैं प्रधान मन्डी के मन को इस बारे में जानता हूं, वे एमरजैसी के डेज में किसी किस्म की ढील बर्दास्त नही कर सकतीं । मैं अपने से पहले बोलने वालों से इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं कर सकता कि यह जो क्रिमिनल नैगलीजैस हुई यह पंजाब के भाइयों की वजह से हुई । उस वक्त मुल्क एज ए होल लथार्जिक था, सारा मु एक अगर मगर की बातों में उलझा हुआ था, जिस वजह से हमारे मसले को सुलझने में सात साल लग गये । मैं बताना चाहता हूं कि 7 केसिज कमिशन के पास पैडिंग थे । जस्टिस शमशेर बहादुर को इस हाई कोर्ट से रिटायर हुए 9 साल हो गये और वे इस किस्म के वाटर डिस्पयूट पर बैठे थे लेकिन उनकी डैथ हो गई । एमरजैंसी डिकलेयर होने से पहले तक सैन्टर के पास आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे डिसप्यूट पड़े थे । तो प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके का पूरा फायदा उठा कर वह तमाम अगर मगर खत्म करके फैसला कर दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, म्उझे उस बुजुर्ग से जो अब दुनिया में नहीं रहे, मिलने का इत्फाक हुआ था । जब वे प्राईम मिनिस्टर के कमरे से निकले थे. इस बात का प्रोटैस्ट करने के बाद कि हरियाणा को ज्यादा हिस्सा दे दिया गया है और पंजाब

को कम दिया गया है । वे ऐसे बुजुर्ग थे जो पंजाब और हरियाणा में ज्यादा फर्क नहीं समझते थे । उन्होंने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो हर बात कही, फैक्टस एंड फिग्गर्ज के साथ कही । इस फैसले के इमीजिएटली तीन दिन के बाद जब पंजाब का डैपुटेशन प्राइम मिनिस्टर से मिला और उन्होंने रि–आर्गेनाइजेशन एकट के मुताबिक पानी के बारे में कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यह इर–रैलेवैट है क्योंकि जिस वक्त भाखडा बना था उस वक्त रि–प्रार्गेनाईजेशन का तो किसी को ख्याल भी नही था और जिस वक्त भाखडा नंगल की अलाइनमेंट हुई थी उस वक्त जिन लोगों को पानी मिलना चाहिये था उनको कम मिला और जिनके पास ज्यादा था, उनको और ज्यादा मिला । मैं दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी. के साथ कहता हूं विरू प्रधान मन्त्री ने उनको ऐसी बात कही थी । प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी फिग्गर्ज थी उन्होने बताया कि कहां सब–सायल वाटर है और कहां नहीं है । प्राइम मिनिस्टर ने पंजाव वालों को बताया कि आप इतना सब–सायल वाटर यूटिलाइज कर सकते हैं और हरियाणा नही कर सकता । तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तमाम दलीलों का जवाब दियाऔर वे वहां से सैटिसफाई होकर चले आए । मैं पहले तो इरीगेशन मिनिस्टर साहिबान से इस बात से डिफर करता हूं कि यह जो मुखालफित है यह एक टैक्नीकल चीज है, हर एक आदमी को अपने दिल की बात कहने का पूरा हक है लेकिन हम एक दूसरे की मुखालफित करे या हमारे में इस किस्म का जजबा हो कि हम जानबूझ कर डिले करे यह नामुमकिन है और वाजिव भी

नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात बहुत कही जा चुकी है कि हमें पानी की सख्त जरूरत है और मैं खुद भी कहता हूं कि हमें तो जरूरत ही पानी की है । मैं चार साल से हमारे बजट को देखता आ रहा हूं जिसमें हम एक ही चीज की कोशिश करते रहे कि अगर इरीगेशन की सहूलियत मिल जाए तो सूबे की काया पलट जाएगी । हम अगर हवाई जहाज से भी उड़ कर हरियाणा के ऊपर से जाएं तो यह पता लगेगा कि हमने दरिया के दरिया खोद कर रख दिये हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हैरानी हो जाती है यह देख कर कि इस इलाके में कितने अरबों की मिट्टी खोद कर हमने पानी लेने की कोशिश की । तो मुझे यह बात नहीं जंचती कि आनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसमें डिले होने देंगी महज इसलिए कि साहब रूल्ज ये हैं, रैड टेपिज्म यह कहता है । जो चोक इंजीनियर या कोई और आफिसर इस किस्म की हिमाकत करेगा वह प्राइम मिनिस्टर सादिबा के गुस्से से टकरायेगा । जहां तक चीफ मिनिस्टर या उनके रिप्रैजैटेटिव का ताल्लुक है अगर वे ऐसा करे गे तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा कितनी कीन हैं वे इसमें कोई रुकावट नहीं आने देगी । अब तो गवर्नमेंट भी दोनों सूबों में एक ही पार्टी की है । यह हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा की सूझ–बूझ का नतीजा है, उनके दिल की उमंग का नतीजा है कि उन्होंने जो मामला इतनी देर से लटकता आ रहा था उसका फैसला कर दिया । पंजाब जिस वक्त इकट्ठा था उस वक्त रावी व्यास का पानी, सतलुज और रावी का पानी जिस तरीके से हमारे पूजनीय स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पंडित

नेहरू ने पाकिस्तान से खरीदा था और भाखडा को भी उन्होंने जन्म दिया था उस वक्त यह सारा पानी पंजाब के इस हिस्से को जो कि अब हरियाणा कहलाता है दिया जाना था । पंजाब और हरियाणा अगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, इकट्ठे होते तो यह सारे का सारा पानी इस इलाके को मिलना था जिसमें से अब बेशतर हिस्सा पंजाब को अलाट हो गया है क्योंकि वह एक सैप्रेट स्टेट बन गई है । तो मैं यह कह सकता हूं कि हमें सैप्रेट स्टेट की वजह से यह घाटा बहुत भारी घाटा रहा है ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : पिछले 20– 22 साल में तो लगा नहीं ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पोलिटिकल बात नहीं करता मैं लाइयर की हैसियत में लीगल बात वाह रहा हूं इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब से गुजरिश करूंगा कि वे मुझे अपनी बात कहने दें मैं नुक्ताचीनी नही कर रहा । तो मैं कह रहा था कि अगर आज पंजाब इकट्ठा रहता तो लीगली जिस वक्त यह पानी की बात चली थी, जिम वक्त पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिये गये थे उस वक्त यह पानी पंजाब के इस हिस्से मै युटिलाइज करने के निए फैसला हुआ था जो आज हरियाणा प्रान्त कहलाता है । यह सारा पानी इस हिस्से को देना चाहिए था, जिसको इरिगेट करने के लिए स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पाकिस्तान को इतनी भारी रकम देकर सैटलमेंट की थी । रही बात यह कि 20 खान में क्यों नही लगा, अगर किसी ने कोशिश

ही न की हो तो लगता कैसे? उस वक्त चौधरी रिजक राम चौधरी रणबीर सिंह मिनिस्टर थे वे बता सकते हैं किं यह क्रिमिनल नैगलीजैस के क्या कारण है । लेकिन एक बात साफ है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा के वक्त मैं अगर आज एमरजैसी न होती तो पंजाब वाले यह फैसला न मानते । उनकी धमको भो आयो कि साहब दो स्टेट्स का डिस्पयूट हो तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है । तो यह बात हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास पहु ची कि उन्होंने. एसा कहा है । प्रधान मन्त्री साहिबा ने उसका जवाब दिया कि यह किस जमाने की बातू करते हो । उन्होंने कहा कि यह दरिया और पानी के रिसोर्सिज सब नेशनल प्रापर्टी हैं इसलिए इस झगड़े को खत्म करो । तो इस फैसले का सबसे बड़ा क्रैडिट, इस झगड़े को खत्म करने का सबसे बड़ा क्रैडिट अगर किसी को जाता है तो वह हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा की सूझबूझ को जाता है जिन्होंने एमरजैंसी की पावर्ज का सही ढंग से इस्तेमाल किया है । हमें भी यह देखना चाहिए कि एमरजैसी ने जो पावर्ज दी हैं, उनको हम नेशनल इंटैरस्ट के लिए यूटिलाइज कर सकें । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं अर्ज किए चाहता हूं कि यह जो मामला है इसमें हमें सैन्टर के मिनिस्टर्ज को ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उनकी पोजीशन ऐम्बै रेसिंग होती है ।

यहां पर कुछ साहिबान ने पंजाब के मिनिस्टर साहिबान और अफसरान के मुताल्लिक खदशात जाहिर किए है मगर डिप्टी

स्पीकर साहिबा मैं यह अज' करना चाहता हूं कि पंजाब केमिनिस्टरों का बड़ा कोआप्रेटिव ऐटीच्यूड रहा है इसलिए इस तरह की तकरीरे करके उनको ऐम्बैरेसिंग पोजीशन में नही डालना चाहिए । मैं आपकी वसातत से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज करुंगा कि अगर कोई डर वाली बात नजर आती है तो वह सारी स्टेट के हैड हें, वे सैटर में जाकर कहें कि हमें थाली बनाए हुए तो इतनी देर हो गई हैं इसमें जो रोटी पडनी है वह नहीं पड़ी, वह न पडी तो इस थाली पर जो खर्चा किया है वह बेकार होगा । इस वक्त हमें पूरी स्पोर्ट मिल सकती है क्योंकि हमारा नेशनल लीडरशिप में भी हाथ है । मैं समझता हूं कि इस काम को पूरा करने के लिए दो साल की देर नहीं लगनी चाहिए क्योकि एमरजैसी में नेशनल इंट्रेस्ट के कामों को हमारी प्रधान मन्त्री हमेशा प्रैफरेंस देती है । जहां तक हमारे इंजीनियर्ज का ताल्लुक है चाहे वे पंजाब के हों चाहे वे हरियाणे के हों वे सारे ही हमारे भाई हैं और वे सारे एक ही स्टाक के हैं । आप सैटर से एमरजैसी पावण' के नीचे एक खास डेट मुकर्रर करवाये और इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक चीफ इंजीनियर हरियाणा से ले ले और एक पंजाब से ले ले' और इस काम को फिक्सड डेट के अन्दर अन्दर कम्पलीट करवायें । इस बात को सब जानते हैं कि पंजाब को पानी की जरूरत नहीं है यह तो आप के टैक्ट पर डिपैडं करता है कि आप कितनी जल्दी इन पावर्ज को जो एमरजैसी की, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने ले रखी हैं, उनको यूटिलाइज करने में आप कामयाब होते हैं । ऐसी कोई

स्टेट नहीं है जिसमें इतनी यूनिटी हो जितनी कि हमारे हरियाणा की विधान सभा में और प्रान्त में है । यहां पर कोई अपोजीशन एलीमेंट इस टाइप का नही है जिस को काम रोकू कहते हैं । अपोजीशन यहां है ही नहीं और इस बारे में कोई आप की अयौरिटी को चौलेंज नही करने वाला । इसलिए मेरा सुझाव है कि इससे पहले कि डिसयूट खड़े हों आप इस काम को जल्दी से जल्दी मूकम्मल करवायें । हम कितने ही केसिज हाईकोर्ट में देखते हैं, काम शूरू होजाता है, दफा 4 के नोटिस इशू होते रहते हैं । आप एमरजैसी की पावर्स को इस्तेमाल करके इस नहर को जल्दी बनवायें । पिछले चार साल में हरियाणा का तमाम वजट इस काम पर लगा हुआ है, उसमें अगर एक दिन की भी डिले हो तो उससे हमें बडा भारी नुकसान होता है जो नहरें हमने खोद रखी हैं वे मुंह फाडे हुए कह रही. हैं कि कब पानी आये और हम चले । उसको आप जल्दी करें! इसके मित्र सारा हरियाणा आभारी होगा । पंजाब के लोगों की, पंजाब के इंजीनियर्ज की । पंजाब के चीफ मिनिस्टर की इस किस्म की कोई भावना नहीं है कि इसमें डिले हो । अगर है तो प्राइम मिनिस्टर के पास उसका इलाज कुए । प्राइम मिनिस्टर यदि चाहें तो साल भर में यह काम हो सकता है । वे जरूर चाहेंगी अगर आप ऐप्रोच करेंगे । इन अलफाज के साथ मैं रैजोल्यूशन के मूवर, चौधरी मेहर चन्द को, मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़े सूटेबल मौके पर यह मूव किया और इस रैजोल्यूशन की ताईद करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैजोल्यूशन आज इस हाउस में पेश हुआ है । अभी दो रोज पहले चौधरी मेहर चन्द के एक सवाल के जवाब में हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने दबी जबान से एक बात कही और हमारे दिल को बड़ा खदशा पैदा हुआ । उनसे पूछा गया कि यह कैनाल जिसके जरिए रावी व्यास का पानी हरियाणा तक पहुंचाया जाएगा, कब तक मुकम्मल हो जाएगी तो उन्होंने फरमाया कि इसकी कुल लैथ 209 किलोमीटर है और तकरीबन आधी लैन्थ हरियाणा में पडती है और आधी लैन्थ पंजाब में । हरियाणा के हिस्से के बारे में उन्होंने फरमाया कि यह दो सीजनों में मुकम्मल हो जाएगी । पंजाब की जब बात आई तो उन्होंने इस तरह के नब्ह इस्तेमाल किए कि मैंने और मेरे साथियों ने यह समझा कि कोई नकोई अडचन इसमें है । मैं इस रैजोल्यूशन के लिए चौधरी मेहर चन्द जी को, जो हरियाणा किसान सैल के इंचार्ज भी हैं और जमीदारों की बात को अच्छी तरह समझते हैं, मुबारिकबाद देता हूं । वे बड़े मौके पर इस रैजोल्यूशन को लाए हैं । इसीलिए मैंने अपना रैजोल्यूशन मूव नही किया । मैं इस बात मैं नही जाना चाहता कि हरियाणा को इसकी कितनी जरूरत है क्योंकि ये बाते पहले ही कही जा चुकी हैं ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी मनफूल सिंह पदासीन हुए) ।

सभापति महोदय, मैं दौलता साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि पंजाब वाले तो हमारे साथ ..... नही करेंगे कालेज के जमाने से मेरा तजुरबा है कि हमारे साथ शरारत होती रही है । मर छोटू राम हरियाणा में एक बहुत बड़ी हस्ती हुई है लेकिन मैने उनके जमाने में भी देखा कि सारी उमर जोर लगाने के बाद सारे हरियाणा में अपने आखिरी दिनों में केवल एक डिग्री कालेज बनवा सके ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : चेयरमैन–साहब, ... शब्द से इनका मतलब रुकावट डालने से है । यह अन–पार्लियामैट्री शब्द प्रोसीडिंग्ज में से निकलवा दिया जाए ।

श्री 'गुलाब सिंह जैन : चेयरमैन साहब., मैं ज्ञानी जैल सिंह जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । मैं उस वक्त से उन्हें जानता हूं जब वे मुझे बतौर वकील जानते थे और मैं उन्हें एक मामूली शख्स के रूप में जानता था । वे एक मीठे शख्स हैं । कभी इन्कार नहीं करेंगे और काम करके भी नहीं देंगे । इस बात को ध्यान में रखते हुए, चेयरमैन साहब, मैं मुख्यमन्त्री जी को इस बात के लिये आगाह कर देना चाहता हूं कि उनकी चिकनी चुपडी बातों में न आएं अगर ये ज्ञानी जो पर डिपैन्ड करेंगे, उनके दफतर में जाना चाहेंगे तो वे कहेंगे कि मैं खुद आ रहा हूं, इनको आने नही देंगे । अगर जबरदस्ती ये पहुंच भी जाएं, जैसे चौधरी बंसी लाल पहुंच जाते थे, तो हमारे मुख्य मन्त्री जी से वह रफनैस लाई नहीं जाएगी और कहीं मीठी बातों में वे फंसा न ले । (विघन

) मैं जानता हूं दौलता साहब, लेकिन मेरे दिल के कुछ खदशात है जिन्हें इस सदन के अन्दर अपने मुख्य मन्त्री के सामने मैं जरूर रखना चाहता हूं । पंजाब वालों ने इससे पहले कब हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, ज्यादती नहीं की । आज वह मजमून नही कि उन सब बातों पर मैं बोल लूं मैं ऐसा कहता हूं कि अगर उनका रवैया दरुस्त होता तो शायद ये दो स्टेट्स अलग–अलग बनने की नौबत न आती । हरियाणा पंजाब अलग नहीं बनता । हरियाणा की आबादी में और पंजाब की आबादी में क्या फर्क है? वही जाट यहां रहते हैं वही जाट वहां रहते है । वहां दाढ़ी है, यहां दादी नहीं है । वहां भी मलिक हैं, यहां भी मलिक है, । वही अग्रवाल वहां हैं, वही यहां हैं । वही दूसरी कौमें और जातियां वहां हैं, वही यहां है । कोई फर्क नहीं लेकिन उनकी नीयत में जरूर फर्क है । हरियाणा का जाट पंजाब के जाट की निस्बत ज्यादा सीधा है और वह इस तरह की बातें जो हमारे साथ पंजाब वालों ने की, कभी करने की जुर्रत नही कर सकता । आज एक बात पंजाब वालों के दिल में है । मैं जरा सख्त बात कहने का आदि हूं । पंजाब वाले यह समझ ते हैं कि हरियाणा की गर्दन हमारे हाथ में है क्योंकि पानी की इनिशियल चौनल जो है वह पंजाब की टैरेटरी में से गुजरनी है । पंजाब वाले यह नही भूले कि वह पानी हमारे हिस्से का है जिसका कि फैसला हो गया है हालांकि दौलता साहब ने फरमाया और मेरे दूसरे साथियों ने भी फरमाया कि जितना पानी हमें मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं । हमको प्राइम मिनिस्टर से इम्माफ नहीं मिला । उन्होंने हमको

पानी दिलवाया, यह उनकी मेहरबानी है । अगर प्राइम मिनिस्टर इन्टरवीन न करतीं तो पंजाब वाले इतना पानी न देते । उन्होंने बहाना लगा लिसा था जैसे दौलता साहब ने फरमाया कि री–आर्गेनाइजेशन ऐक्ट के अन्दर हरियाणा के पानी का जिक्र नही हालांकि हर आदमी जानता है, रिकार्ड पर यह चीज है, मेरे साथी बतलाया करते हैं जो उस वक्त की सरकार में थे कि यह जो स्कीम बनी थी इसके अनुसार सारेका सारापानी हरियाणा के हिस्से में आना था । हम समझते थे कि हमको पूरा पानी नहीं मिला लेकिन जिस चीज का फैसला एक आगस्ट बौडी ने दिया उसको हमने सरे तसलीम खम किया । फिर दौलता साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें तो एक मिनट में फैसला कर देंगी कि चौनल खोदे लेकिन आखिरकार यह फिजीकल काम है इसमें समय लगेगा । एक–एक मिनट की देरी की तरफ मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे लिए यह बहुत ही खतरनाक है । आज सारे हरियाणा का किसान जिस वक्त मंडियों में जाता है, देहात में जाता है, वह यह बात करता है कि कब रावी व्यास का पानी आए और कब हमारा वाटर अलाऊंस इंक्रीज हो । आज हरियाणा का किसान पानी के लिए रो रहा है । आज पंजाब इसमें देरी करेगा । क्योंकि जबतक यह चौनल नहीं बनती उस वक्त तक वह इस पानी को इस्तेमाल करना चाहेगा । कैसे करेंगे? जब पानी उनके पास पहुंच जाएगा, हमारे यहाँ चौनल बनी हुई नही होगी, वह सैन्टर को कहेंगे, कसूर. हमारा निकालेंगे क्योंकि हमेशा पंजाबी हरियाणा वालों से ज्यादा होशियार रहा है । वे कहेंगे कि

इन्होंने ऐसा नही किया, वैसा नही किया और फ लौ बात नही की । मैं मुख्य मन्वी जी को आगाह करना चाहता हूं कि इन सब बातों को पूरी तरह ध्यान में रखें और आंख खोल कर, दिमाग को तरोताजा रख कर खतोखिताबत करे । मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं । जो सख्त बात का मैंने जिक्र कियाथा, कुछ भाई सोच रहे होंगे कि वह क्या है । मैं पंजाब वालों को वार्निंग देना चाहता हूं । अगर हमारे पानी का रास्ता उनकी टैरेटरी में से पड़ता है तोप जाब वाले सुन लेकि दिल्ली आदि जाने के लिए उनका रास्ता भी. हरियाणा में से पड़ता है । यह बात उनको भूलनी नहीं चाहिए । इस तरह की कफन्टेशन, शरारत की बात उनको करनी नही चाहिए । अगर उन्होंने ऐसा किया तो हरियाणा का एक एक बच्चा, जवान और बूड़ा इस बात के लिए मजबूर हो जाएगा कि हम किसी पंजाब वाले को हरियाणा की टैरेटरी में से गुजरने न दें । अगर वे हमें मारना चाहते हैं तो हम भी उन्हे जिन्दा नही रहने देंगे । पानी आज हमारी जिन्दगी का सवाल बना हुआ है । ये हमारे जजबात हैं और इन जजबात को मैं चाहता हूं इस सदनमें रखा जाए । मैं आशा करता हूं कि दूसरे साथी भी मेरे साथ मुलफिक होंगे । मैं अपने मुख्य मन्त्री. जी से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि वे हमारे इन सैंटिमैन्टस को मोहतरिमा प्राईम मिनिस्टर तक पहुंचा दें और उनसे कहे कि बहिन जी जल्दी से जल्दी पंजाब वालों को– इस काम को करने के लिए मजबूर करे । मेरी यह भी दरख्वास्त है कि वह चौनल बनाने का काम जहां तक हो सके हरियाणा के इंजीनियर्ज के जिम्मे लगना चाहिए । हमारे यहां इस

सदन में मेरे एक दोस्त मैम्बर चौधरी हरकिशन लाल जी होते थे । वे हमेशा सुखचौन रजवाहे का रोना रोते रहते थे' । उसमें पंजाब से पानी आता था । वे पानी रोक लेते थे । उनका हल्का पानी के लिए तरसा करता था । इसलिए इस बारे में भी मुझे पूरा खदशा है कि वे शरारत करने से नही हटेंगे । अगर मुख्य मन्त्री जी का जबाव चौधरी मेहरचन्द जी के सवाल के जवाब में सीधा होता तो हम सोचते कि सब चीज ठीक है, काम ठीक चल रहा है, चौनल खुदनी शुरू हो जाएगी, हम इतना रुपया इनवैस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन ने हमारी चौनल को मजीद रुपया मंजूर किया है । जिसे हम जमुना सिस्टम में वाटर अलाउन्स बराबर करने में इस्तेमाल करेंगे । जो हमारी लिपट इरीगेशन कैनाल हैं उनको भी पानी दिया जायेगा । कुछ बचा–खुचा पानी भाखडा कैनाल में दिया जायेगा या और दूसरी जो स्कीमें मंजूर कर रहे हैं उनके लिए यह पानी इस्तेमाल किया जायेगा । प्रधान माली महोदया ने हमारे पानी का फैसला कर दिया । उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे यहां का सब–सायल वाटर ब्रैकिश है, इन सब. हालात को देखते हुए और हमारे काज को जस्टीफायी समझते हुए, उन्होंने हमारे क्य में फैसला किया. । पंजाब वाले तो हमें रत्ती भर भी पानी देने के लिए तैयार नहीं थे । अब सवाल यह है कि वै चौनल के खोदने में रुकावट पैदा न करे लेकिन इस बारे में हमें इस बात से जाहिर हुआ कि जब चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां एक सवाल के जवाब में बताया कि अभी. कई चीजों का फैसला होना है । तो हमें इस बात से सन्देह होता है कि कुछ न कुछ दाल में

काला है । मैं मु ख्य मन्त्री जी और बहिन इन्द्रा जी से आपके जरिये रिक्वैस्ट करूंगा कि इन चीजों का भी जल्दी से जल्दी फैसला करवायें । अगर यह फैसला जल्दी नहीं हुआ तो वही बात होगी कि विवाह तो हो गया मुकलावा हुआ नहीं, तो उस विवाह का क्या लाभ हुआ । मैं समझता हू कि मेरे सैंटीमेंट के साथ सभी साथी सहमत होंगे । मैं ज्यादा न कहता हुआ आखिर में मुख्य मन्त्री को आगाह करना चाहता हूं कि वे ज्ञानी जी की चिकनी–चुपडी बातों में– बिल्कुल न आयें और इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करें । वे चाहे सीधे प्राइम–मिनिस्टर. से बात करें या चाहे मु ख्य मन्त्री ज्ञानी जैल सिंह जी से बात करें, इस चौनल को खुदवाने के काम में बिल्कुल देर न करें और इस काम को डेट बाउन्ड कराने का प्रयत्न करें । डेट बाउन्ड न होगा तो हम इस मामले में कामयाब नहीं हो सकेंगे । जैसा कि दूसरे साथियों ने कहा है कि हमारी सरकार इस हालत में अगर पानी को वक्त पर लेने में कामयाब नहीं हुई तो हरियाणा के लोग इस सरकार को माफ नहीं करेंगे, मैं भी माफ नहों करू गा । मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि यह बहुत अहम मामला है । मैं चौधरी मेहरचन्द जी को मुबारिकबाद देता हूं और लोग भी दे रहे हैं कि वे एक अच्छा रैजोल्यूशन, हरियाणा की भलाई के लिए लाये हैं । इस रैजोल्यूशन के आने से सदन काफी सारियस है, मुख्य मत्री को चाहिए कि इस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करें २ जैसा कि यहां मुख्य मस्ती जी ने बताया थो कि यह चौनल दो सीजनज के अन्दर हरियाणा के एरिया में कम्पलीट हो जायेगी तो मैं साथ साथ यह

भी रिक्वैस्ट करूगा कि पंजाब के पार्ट में भी यह साथ साथ कम्पलीट हो जानी चाहिए । अपार पंजाब की कम्पलीट न हुई तो हरियाणा के पार्ट में जो पैसा लगेगा वह भी बेकार जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस रैजोल्यूशन की पुरजोर शब्दों में ताइद करता हूं ।

चौधरी अमर सिंह (बवानी खेड़ा) : चेयरमैन साहब, आज जो प्रस्ताव हाउस के सामने चौधरी मेहर चन्द जी ने रखा है, मैं उसकी ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज हरियाणा की जनता इनके पीछे लगी हुई है कि पानी किसी भी तरह से हमें दिया जाये । हरियाणा किसानों का प्रान्त है । हरियाणा की सारी की सारी भू मि कुरुक्षेत्र और करनाल को छोड़ कर टीबे वाली है या ऐसी है जिसमें पानी नहीं लगता है । मैं तो यह कहूंगा कि मूवर आफ दि रैजोल्यूशन ने यह प्रस्ताव मूव करके लोगों की सही दिक्कत को पहचाना है । मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने सही ढंग से हरियाणा की आवाज को आगे तक पहुंचाया है । हम लोग बार बार यह कहते रहते हैं कि जरूरत के मुताबिक पानी मिलेगा । हरियाणा के अन्दर जितने ट्यूबवैल्ज लगने थे लग गये । हरियाणा के अन्दर अब कोई और– दरिया नहीं है और यह जो रावी व्यास का पानी मिलना है इसमें अगर रुकावट पड़े तो फिर हरियाणा के लोगों के पास चारा ही कग रह जाता है । मैं यह बात कहते हुए बिल्कूल गुरेज नहीं करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के साथ हमेशा से ही ज्यादती होती रही हुऐ । हिन्दुस्तान 15 अगस्त

सन् 1947 को आजाद हुआ था लेकिन हरियाणा का जन्म नवम्बर 1986 में हुआ । इससे पहले इस इलाके को पंजाब और हिन्दी रीजन में बांटा जाता था । उस वक्त हिन्दी रीजन को जो भी पैसा दिया जाता था वह 31 मार्च तक सरप्लस ही दिखाया जाता था । अन्त में जा कर उस पैसे के पंजाबी रीजन के जिले जालन्धर और अमृ तसर मे खर्च कर लिया जाता था हमने उस टाईम पर काफी सबर किया । हम इन सारी बातों को बरदास्त कर रहे । जो पंजाब के भाई हैं वे पंजाबी रीजन में रहते हैं और हम हिन्दी रीजन में रहते हैं लेकिन हम दोनों यहां इकटठे भी रहे फिर भी उन ज्यादतियों को बरदास्त करते रहे । बंटवारे के टाईम पर भी हमारे साथ ज्यादतियां होती रही । बंटवारा क्यों हुआ था? बंटवारा राजनैतिक स्थिति को देखते हुए हुआ था । हिमाचल प्रदेश अलग बन गया और हरियाणा प्रदेश अलग बन गया । हरियाणा की आबादी 78 लाख की है । चेयरमैन साहब, आपको पता है कि बंटवारे के लिए जो बाउन्डरी कमीशन मुकर्रर हुआ था, उसके फैसले के आधार पर भी हमें पीछे रखा गया क्योंकि जो हिस्सा कमीशन ने हमें दिया था वह भी नहीं मिला । यहां तक कि हिन्दी भाषी इलाका भी काफी पंजाब को चला गया । आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात पर उतारू हैं कि हम ये ज्यादतियौ कब तक बरदास्त करेंगे । वे मान भी किस तरह से सकते हैं? पानी किसान की जिन्दगी का आधार है । किसान खेत में पानी ही नही देगा तो पैदावार किस प्रकार से हो सकती है । बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत एक प्वायंट इसमें यह भी है

कि हर एक का दो–अढाई एकड़ में जरूर पानी देंगे । अगर इस चौनल की सही टाइम पर नहीं बनाया गया तो पंजाब के भाई अवश्य ही रूकावट डालेंगे । प्रधान मन्त्री जी के बीस सूत्री कार्यक्रम में लिखा है कि 12– 14 लाख एकड़ भूमि को नया पानी मिले । इसके अनुसार जो हमारे इलाके पानी की बाट देख रहे हैं, अगर उनको पानी नही दिया गया तो इस बीस सूत्री कार्यक्रम का जो प्रस्ताव रखा है फिर यह कागजों पर ही रहेगा । पंजाब की जनता और हरियाणा की जनता आपस में कोई बिटरनैस पैदा न करें । हरियाणा केलोग पटियाला में जाये या पंजाब के लोग रोहतक में जायेतों कोई फर्क नही पडता । दोनों प्रदेशों के लोगों का अच्छा सम्बन्ध रहे लेकिन हरियाणा इस बात को बरदास्त नहीं करेगा कि उनको पानी न मिले । मुख्य मन्त्री ज्ञानी जैल सिंह हों चाहे कोई और इस रास्ते रुकावट में डाले तो बरदास्त नहीं किया जायेगा ।

चेयरमैन साहब आपक याद होगा कि जब कामरेड रामकिशन जी मुख्य मन्त्री थे उस टाईम पर यह प्रस्ताव आया था कि हिन्दी रीजन में पानी कम है इसलिए इस इलाके को पूरा पानी दिया जाये । यहां इंटेन्सिटी आफ वाटर बहुत कम है और पंजाब के अन्दर हंड्रेड परसेन्ट कमान्ड एरिया है और हंडेरड परसेन्ट इरिगेशन है लेकिन हरियाणा के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं है । मैं 196 2– 1967 तक असैम्बली का मैम्बर रहा हूं । मुझे याद है जब राम किशन चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे । तो उन्हेंने कहा था कि

मैं मानता हूं कि लुधियाना और अमृतसर के मुकाबिले में हिन्दी रीजन में वाटर अलाउ स कम है । जब रावी ब्यास के पानी का फैसला हो जाएगा तो हिन्दी रीजन को पूरा हिस्सा मिलेगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी । यह अश्योरेंस उन्होंने आन दि फ्लोर आफ दि हाउस दिया था कि पहले हिन्दी रीजन को पूरा पानी मिलेगा और उसके बाद पंजाबी रीजन को पानी मिलेगा । लेकिन आज हेराफेरी करके, तोड़ मरोड़ कर कोशिश की जा रही है कि ओल्ड अलाइनमेंट की बजाए नई अलाइनमेंट कराकर हाई कोर्ट में किसी तरह से रिट हो जाए और हरियाणा इस चौनल को पूरा न कर सके। इस बात को हरियाणा की जनता कभी बरदाश्त नही करेगी और इस बात के लिए हमारी गवर्नमैंट को तनिक भी इन्तजार नहीं करना चाहिए । आज पंजाब के भाइयों को सोचना चाहिए कि हरियाणा के ग्यारह जिलों में से तीन जिले अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेव जो सब से अच्छे जिले हैं वहां पर भी लुधियाना, अमृतसर और जालन्धर के मुकाबिले में वाटर अलाउन्स कम है । इन जिलों में हंड्रैड परसेन्ट इरिगेशन है लेकिन वाटर अलाउन्स पंजाब से फिर भी कम है । बाबू गुलाब सिंह की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं जैसा कि गहोने चण्डीगढ के मसले पर अपनें विचार प्रकट किए कि हरियाणा कै लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार. हैं अगर उनके साथ कोई अन्याय होता एं । 1857 का गदर इस बात की शहादत है कि उस समय हरियाणा के लोगों ने कितनी कुर्बानी की थी । जितने भी मुसलमान बादशाहों ने हिन्दुस्तान पर हमला किया वे बेरोक टोक बढ़ते चले जाते थे

लेकिन जब पानीपत के नजदीक आते थे तो यहां पर उनकी बहुत पिटाई की जाती थी । चेयरमैन साहब, हम यह नहीं चाहते कि आपस में लड़े' । हम चाहते हैं कि दोनों भाइयों के अन्दर कोई बिटरनैस पैदा न हो लेकिन हरियाणा के लोग इस बात को बरदाश्त नही करेंगे किं उनके साथ कोई बेइन्साफी की बात हो । हम प्रधान मन्त्री के फैसले का स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारी कठिनाइयों को देखते हुए फैसला दिया । यदि एमरजैन्सी लागू न होती तो शायद प्रधान मन्नी यह–फैसला इस समय न करतीं लेकिन एमरजैन्सी के होते हुए और 20 सूत्री कार्यक्रम के होते हुए, जिसमें यह कहा गया है कि अनाज की औदावार बढ़ानी है, खाली जमीन में पानी देना है, सिंचाई के साधन बढ़ाने हैं अगर कोई इस 20 सूत्री कायक्रम में रुकावट डालता है तो उसके पार्ट पर यह क्रिमिनल नेगलीजैन्स है । अगर हमारी चौनल बनाने में कोई रुकावट डालता है तो वहठीक बात नहीं है । मैं ज्ञानी जी से गुजारिश करना चाहता हूं मैं उनके साथ पांच साल तक एम० एल० ए० रहा हूं, मुझे पता कुरु वह बहुत मीठे हैं और बात करने में पूरे हैं लेकिन अगर 20 सूत्री कार्यक्रम जो प्रधान मन्त्री ने स्वयं बनाया है उस पर अमल नही करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वें प्रधान मन्त्री को मुखालफित कर रहे हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम में देहात में नई जमीनों को पानी' देने का योजनाबद्ध कार्यक्रम है और उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हरियाणा की भूमि 'में पानी आना है अगर उसमे कोई रुकावट डालता है तो यह बरदाश्त नहीं किया जाएगा । चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये यह

गुजारिश करना चाहता हूं कि यह चौनल 1970 में पूरी हो जानी चाहिए थी । आपको भली भांति याद है कि जब भी हम जनता के सामने जाते हैं तो 'वहां लोग पूछते हैं कि रावी व्यास का पानी कब आएगा । हरियाणा के लोगों को इस पानी का बहुत बेताबी से इन्तजार है । हरियाणा में कई साल से सब–सावल बाटर डाउन चला गया है और जिन गांवों में मीठा पानी था वहू खारा हो गया है । आज भी हरियाणा के अन्दर यह हालत है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है और 'बहुतें से गावों में जहां पशु पानी पीते हैं वहीं से इन्सान पानी लेते हैं । अगर ऐसी हालत होते हुएभी कोई रुकावट डाले तो वह अच्छी बात नहीं है । मैं सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो पंजाब के एरिया में न्यु अलाइनमेंट बिल्कुल न मानी जाए क्योंकि वह न्यू अलाइनमेंट की बात उठाकर एक नई चीज पैदा करना चाहते है और जो ओल्ड अलाइनमेंट है उस बात से हटना चाहते हैं । न्यू अलाइनमेंट पर रिट करा कर मामले को लटकाना चाहते हैं । दूसरी बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम पंजाब के एरिया के अन्दर होना है, जो नहर हमें बनानी है उस नहर का काम हमारे हरियाणा के इंजीनियर करें । पंजाब सरकार तया 'हरियाणा सरकार दोनों को इस चीज के लिए राजी होना चाहिए । अगर पंजाब दो भाई इस बात से मुत्तफिक न हों तो सरकार हरियाणा की जनता के जजबात को देखते हुए प्रधान मन्त्री से मिले और इस मामले को जल्दी सुलझाए क्योंकि हरियाणा के लोग अब इस बात को ज्यादा –देर तक बरदाश्त नहीं कर सकते ।

चेयरमैन साहब, बहुत सारे लोगों के अन्दर इस बात की चर्चा है कि पंजाब के लोगों ने इस बात का एलान किया हैकि हम हरियाणा के जो इंजीनियर हैं उनको अपनी भूमि पर नहीं आने देंगे और न नहर खोदने देंगे । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाया है उसको समय पर पूरा किया जाए । जितने अर्से में हरियाणा के अन्दर नहर बननी है उसी असें में पंजाब के एरिया वाली भी नहर पूरी हो जानी चाहिए । अगर पंजाब के एरिया के अन्दर हमारी चौनल नही बनती है तो हरियाणा के अन्दर पानी नहीं आ सकता है । चेयरमैन साहब, आपके जरिए मैं पुरजोर लफजों में इस सरकार से अपील करना चाहता हु कि इस काम को जल्दी पूरा किया जाए । सारा हरियाणा इस मामले में आपके हुक्म का इन्तजार कर रहा है । एक–एक बच्चा पानी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है । चेयरमैन साहब, इन शब्दों के साथ चौधरी मेहर चन्द ने हरियाणा की नब्ज पर हाथ रखकर जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । चौधरी मेहर चन्द वक्त की आवाज पहचान कर इस अहम मसले पर इस प्रकार का जो प्रस्ताव लाए है यह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, यह जो रावी और व्यास लिंक के पानी का फैसला हुआ है यह एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इस बात का हम सालों

से इन्तजार करते रहे हैं और हमारे दिल में यह हसरत थी कि इस का फैसला हो जाए लेकिन बार बार इस में– हमारे पंजाब के भाई अडचने पैदा करते रहे । अब इस बात का श्रेय जो है वह हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा को जाता है कि उन्होंने हमारी जरुरत को देखते हुए यह फैसला करवा दिया । चेयरमैन साहब, एक बात पर हमने अपने दिल की तसल्ली का इबहार किया है, एक बात खुशगवार की है कि हाउस में संजीदगी है । हमारा जो पड़ोसी भाई पंजाब एं, वहां के सब लोगों को हम जाति तौर पर जानते हैं, उनके इलाके, हमारे इलाकों से मिले जुलै हैं, बहुत सी रिश्तेदारियां हमारी वहां और उनकी हमारे साथ हैं । हमारा उनके प्रान्तों गे आना जागा और उनका हमारे प्रान्तों में आना–जाना है, बिल्कुल समान रीति रिवाज हैं । चेयरमैन साहब, राज्य स्तर पर कब कोई मसला उनकी और हमारी सरकार के दरिम्यान होता है तो हमें उस पर सघर्ष करना पड़ता है और फिर उस संघर्ष के बावजूद हम फेल हो जाते है । आप पिछले सैशनों की कार्यवाही निकाल कर देख लेवें, चण्डीगढ और फाजिल्का– अबोहर के मामले पर, जो नान आफिशियल डेज में बहस हुई उसमें इस फैसले के लिये सरकार रो पुरजोर माग करते रहे कि हमारी परपोजल को आप गवर्नमैंट आफ इंडिया तक पहुंचा देवें लेकिन वह बात आज तक पूरी नही हों सकी और आज ये उन्ही लाइनों पर किर चल रहे है । चेयरमैन साहब, आज हरियाणा प्रान्त ने अपने आपको तैयार कर लिया है किसान ने काम करने के ढंग को अच्छी तरह से महसूस किया है । आज अगर हिन्दुस्तान के नक्शे पर हरियाणा

का किसान यह तजवीज लेकर चल पड़े कि वह अग्रसर होकर खेती–बाड़ी करके अपना नाम पैदा करेगा तो फिर हरियाणा का नाम सारे हिन्दुस्तान में चमकेगा । चेयरमैन साहब, आप देखिए पानी का फैसला हो चुका है और हमारे हक में हुआ है और तब भी हम 30–35 परसैन्ट पानी का इस्तेमाल करते हैं जबकि पंजाब में 60, 70, 80 और 100 परसैन्ट पानी उनके एरिया में पड़ता डेए । तो आप बताएं कि हमारे साथ वह कितनी बेइन्साफी है । चेयरमैन साहब, हम यह चाहते हैं कि हमें अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिये ताकि हरियाणा का एक. कच्चा भी उन पर यह उंगली न उठाये कि पंजाब वाले हमारे साथ भेदभाव रखते हैं । पंजाब वाले तो हमारे भाई हैं, उनको तो हमारी तरक्की से खुशी होनी चाहिये । इन बातों के लिये हम लड़ते फिरें, यह कोई अच्छी बात नही है । हम इस मामले पर अपने चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ मजबूत करने के लिये सदा तत्पर हैं लेकिन जो खदशात हमारे सामने आए और अब पंजाब के भाई जो रिटें दायर करवाना चाहते हैं कहते हैं कि हम नई एनलाईनमेंट करेंगे, ये सारी बातें चेयरमैन साहब, अगर किसी अन्धे के सामने भी रखी जाएं तो वह भी यह कहेगा उनके मन में जरूर कोई फर्क आ गया है । चेयरमैन साहब, आज तमाम हिन्दुस्तान पर, तमाम पार्टियों पर एमरजैन्सी का असर हुआ है और आज जो हालात पैदा हो गये हैं उनकी देखते हुए अगर मैं यह कहूं कि पंजाब के भाईयों के दिमाग पर कोई असर नही है तो शायद मैं गल्ती पर नहीं हूंगा । उसे हमारी आज की हालत को महसूस करना चाहिये । चेयरमैन

साहब, आज हमारे तीन– चार जिलों में पानी की इतनी किल्लत है कि जिसके कारण हमारे आपस में मनमुटाव हैं । पानी थोड़ा है और उसको बांटना पड़ता है ।

चेयरमैन साहब, आप अन्दाजा लगाएं, हम और आप लोग अब चण्डीगढ में बैठे हुए है । हर रोज हमारे दिमाग में यह बात रहती है कि बारिश नही हुई । हम सब के सब महसूस करते हैं कि अगर पांच–दस दिनों तक बरसात न हुई तो हमारे साथ क्या हालात बीतेगें । हम इस लिये कहते हैं कि हरियाणा की भूमि सोना पैदा कर सकती है मगर पानी की कमी के कारण बेचारे किसान आसमान की ओर देखते हैं । चेयरमैन साहब अगर इन्साफ हो जाए और उसको इम्पलीमेन्ट न करें तो यह इन्साफ नहीं होगा । अतरू मैं इन बातों को कहते हुए यह चाहता हूं कि हमारी सरकार हमारी इस आवाज को प्राइम मिनिस्टर साहिबा तक पहुंचा दे कि हरियाणा का किसान पंजाब के किसान का मुकाबिला करके आगे आना चाहता है, इसलिये हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिये । चेयरमैन साहब मैं यह बार–बार कहूंगा कि जो जमीन एकवायर होगी, उसकी कीमत हमें देनी होगी इसलिये उस पर हमारा पूरा कन्ट्रोल होना चाहिये और यह सारा काम हमारे काबिल इंजीनियर्ज की देख–रेख में ही होना चाहिये । इस में कोई शक नहीं कि हमारे इंजीनियर की टीम किसी भी अंडरटेकिंग को अन्नने ऊपर ले सकती है और उसे कर सकती है । यह हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है क्योंकि पानी के बगैर हमारी पैदावार नहीं

बढ़ सकती और न ही इंडस्ट्री ही लग सकती है । हमारे प्रान्त में ऐसे इलाके हैं जहां पर चाय भी नहीं बन सकती क्योंकि वहां पर पानी की बड़ी किल्लत है । इस तकलीफ से तमाम लोगों को., चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजिनैस मैन हो बहुत फर्क पड़ेगा । चेयरमैन साहब, यह सारी जो बातें मैंने अभी अज' की हैं ये सेन्टर की मदद के बगैर नहीं बनेगी । पंजाब वाले इस काम में जान बूझकर देरी कर रहे हैं । अतः हमारी आवाज जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर साहिबा तक पहुंचाई जाए । मै चौधरी मेहर चन्द जो के इस रेजोल्मूशन की ताइद करता हूं और खदशात जाहिर करता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार चंण्डीगढ, फाजिल्का और अबोहर का मामला अभी तक लटका पड़ा है, उसी तरह यह मामला भी न लटक जाए । अगर हम इस काम में और कोशिश करते रहे और इस बात के लिये मन में मजबूती कायम करें तों यह ऐतिहासिक काम होगा । मुझे इस बात की खुशी होती है कि हरियाणा किसी तरह से किसी से कम नही है । यहां पर कितने करोड़ रुपये लगा कर नहरों कौ जाल बिछा दिया गया है और सिर्फ उसी पानी की ये नहरें इन्तजार कर रही है । अगर वह पानी न आया तो आप अन्दाजा लगाए कि इतना भारी कर्जा हमारे ऊपर जो चढ़ा हुआ है, करोड़ों रुपये, साल का, वह कैसे पूरा होगा? वह कर्जा अगर इसी तरह रहा तो हमारी इकोनोमी को कितनी ठेस लगेगी । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह हमारे सैंटीमैंटस प्राइम मिनिस्टर साहिबा तक पहुंचाए और इस बात की पूरी कोशिश करवाए कि यह लिंक जल्द से जल्द पूरा हो जाए ।

7.00 बजे ।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला अनुसूचित जाति) : चेयरमैन साहब, यह प्रस्ताव जो हाउस के अन्दर आया है, यह हरियाणा के लिये एक बहुत ही खुशी की बात है । अभी. अभी हमारे म्उख्य मन्त्री जी ने इस सैशन में हाउस के अन्दर बताया था कि हम रावी और व्यास के पानी को दो साल के अन्दर–अन्दर नहरों को दे पाएंगे और हरियाणा की तमाम गरीबी को हटा देंगे । मुझे इसे बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कही और हमारे पहले मुख्य मन्त्री जी भी इस तरह की बातों को पूरा करने में पूरे सफल हुए जिसकी वजह से हरियाणा में तरक्की हुई । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जब यह बात कही थी कि यह पानी हमारे हरियाणा में आएगा तो हमें बड़ी खुशी हुई लेकिन आज का यह प्रस्ताव आने से मुझे कुछे– सन्देह हुआ कि इसके अन्दर पंजाब की तरफ से कोई न कोई अडचन पैदा हुई है या पंजाब वालों की हरियाणा वालों के ऊपर कुछ सख्ती की नजर दिखाई दी है । मैं इन पंजाब वाले भाइयों से यह निवेदन करता हूं कि हरियाणा के लोग तो पहले से ही इतने गरीब आदमी है कि दो टाइम 'पेट भर कर रोटी भी नहीं खा सकते और जो हरिजन हैं, बैकवर्ड हैं या बगैर जमीन वाले खासे तं और पर वे लोग इस पानी पर बड़ी भारी आशा करते थे कि पानी आएगा और जो बबर जमीनै है उसको पानी मिलने की वजह से सबको पेट भर रोटी मिल सकेगी 1 वे आदमी जिनको आज

मजदूरी भी हीं मिलती और आज जिनके लिये काम करने का स्थान नहीं है उनको भी काम मिलेगा । पहले जब नहरें खुदी थी तो कुछ दिन उन्हे मजदूरी मिल गई और अबे उन्होंने सोचा था कि पानी आएगा तो खाने को कुछ मिलेगा । लेकिन आज हालत यह है कि हिसार के अन्दर केवल एक फार्म है । उसके अन्दर हरिजन भाई मजदूरी करने के लिये जातें हैं । वहां पर सात रुपये मजदूरी फिक्स होने के बावजूद भी उनको साढ तीन रुपये मर्द को दिये ते हैं और औरत को ढाई रुपये दिए जाते है । इसलिये अगर यह पानी आ जाता तो यह नौंबत न आती । कुछ दिन पहले हमरि 'भाई अमर सिंह जी ने भी कहा था कि ये हरिजन इतने दुखी हैं कि उनके खाने के लिये अरहर तक नहीं हैतो वह बात उनकी ठीक थी क्योंकि आज तमाम की तमाम हालत ऐसी हो चुकी है 1 उनके पास जमीन भी नहीं है और न ही कोई और साधन है । तो मैं इतना ही कहते हुए मु ख्य मन्डी जी से यह कहूंगा कि हम तमाम हरियाणा के बाशिन्दे इस मामले में आपके साय हैं और हरियाणा के लिये यह जिन्दगी और मौत का सवाल है । आप हमारी इस भावना को प्रधान मन्त्री तक पहुंचाएं कि पंजाब वाले हमारे साथ ज्यादती करते हैं । अभी मेरे भाई फूल सिंह जी ने भी बताया कि वे हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं और इसमें बाधा डालने जा रहे हैं । तो यह बड़े दुख की बात है इस बात के लिये हम पीछे नहीं हटेंगे । आप इसके लिये कोशिश करें हम सब आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है । इसमें अपोजीशन का कोई सवाल नही है क्योंकि यह हमारे तमाम हरियाणा के हित

की बात है । इसलिये मैं आपको फिर प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी इस भावना को प्रधान मन्त्री तक पहुंचाएं हम आभ–से कमी भी पीछे नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

चौधरी शिव राम बर्मा (नीलोखेडी) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव आया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इसकी जितनी आवश्यकता आज हरियाणा को है मैं समझता हूं कि शायद किसी वक्त भी किसी ने इतना महसूस नहीं किया था । आज हरियाणा के अन्दर पानी की इतनी कमी है कि सारे हरियाणा में एक एकड़ भूमि को भी एश्योरड इरीगेटिड रकबा नहीं कहा जा सकता । वर्षा न हो और दो फसलें पूरी पैदा हों तो उसे एश्योरड इरीगेटिड रकबा कहाजा सकता है, एश्योरड इरीगेटिड लैड असली वह हो सकती है जिसमें बिना वर्षा के दोनों फसलें पूरी पैदावार दें । तो आज सारे हरियाणा में एक एकड भी जमीन ऐसी' नहीं है । इसका कारण यह है कि जब पंजाब और हरियाणा इकट हा था तो उसी समय से हमारे साथ यह भेद–भाव रहा है । उस समय पंजाब में पानी ज्यादा जाता रहा और हरियाणा में बचा–खुचा जाता था इसलिये आज यहां की कई लाख एकड़ जमीन पानी के लिय' तरस रही है औज सतलुज ब्यास का जो प्रोजैक्ट है वह जून 1977 में पूरा होने जा रहा है । इसलिये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो पीनी हमे नहर के जरिये

लाना है उसे लाने के लिये सतलुज यमुना लिंक नहर जून 1977 तक पूरी हो जानी चाहिये । क्योंकि इसकी लम्बाई भी कोई थोड़ी नही है, वह 209 किलोमीटर लम्बी है, वह थोड़े समय में मुकम्मल होनी आसान नहीं है, इसलिये अभी से सरकार प्रयत्न करे तो यह काम पूरा हो सकता है । यदि यह नहर पूरी नही होती तो जिस तरह से रावी का पानी पाकिस्तान को जाता रहा उसी तरह से सतलुज व्यास का पानी भी पंजाब में जाता रहेगा । कई हमारे माननीय दोस्तों ने कुछ कडे शब्द भी पंजाब के लिये कहे लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा कोई अलग अलग देश नहीं हैं, ये एक ही देन के दो प्रान्त हैं, हम आपस में भाई भाई हैं और हमारी और उनकी कोई लड़ाई नही है । अगर हम लड़ाई की भाषा बोलेगे तो न वह हमारा कुछ बिगाड़ सकेगे और न हम उनका कुछ बिगाड़ सकेंगे । इसलिये यह जो फैसला केन्द्रीय सरकार के हारा हुआहै यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मे– दारी हो जातीहै कि उस पर वह अमल करवाए साथ ही हरियाणा पंजाब तथा केन्द्र में कांग्रेसी सरकारें हैं इस लिए कांग्रेसी सदस्यों को ऐसी भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी । मैं समझता हूं कि जितनी खुशी कई साथियों ने मनायी है कि हमें बहुत भारी मिकदार में पानी मिला है, बड़ी कामयाबी हुई है मैं उनसे सहमत नही हूं । मैं समझता हूं कि हमें पूरा हिस्सा अभी भी नही मिला । हमें जहां 10 रुपये में से 6 रुपये मित्रने चाहिए थे वहां हमें तीन साढ़े तीन रुपये मित्ने हैं इसलिए हमारा जो बाकी हिस्सा रह गया है मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि

उन्हें केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लानी चाहिए कि हमारा जो हिस्सा बाकी पड़ा है, वह हमें दिलाया जाए । पहले भी जितने प्रोजेक्टस बने हैं उनका अगर हिसाब लगाकर देखें तो जितना पानी हमें मिलना चाहिए था उससे आधा हमें मिला है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो पानी हमें मिला है जब ये नहरों में आ जायेगा तो उससे भी सारी भूमि को हम सिंचित नही कर सकेंगे 1 इसलिए जितना हिस्सा हमारा और बनता है उस की मांग भी हमें जारी रखनी चाहिए ताकि हम पूरी पैदावार कर सके । इसके अलावा जो पीने के पानी की कमी है जब नहरों में पानी आ जायेगा तो बहुत से इलाके में जहां खारी पानी है वह स्वयं ही मीठा हो जायेगा और वहां शायद वाटर वर्क्स की भी जरूरत न पड़े और जहां पर यह समस्या ऐसे हल नहीं होगी वहां उन्ही नहरों से वाटर वर्कस के जरिये से लोगों को पीने के लिए पानी दिया जा सकता है । इसलिए जो हमें पानी मिल रहा है उसे लाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयत्न किया जाये । लेकिन जिस तरह हमारी पीछे ढील रहीहै, चण्डीगढ का मामला आया उस पर भी हमने बड़े जोर जोर की तकरीरे की थीं, कई भाइयों ने चौलेंज भी किए थे लेकिन उसके बाद नतीजा जो हुआ आपके सामने है सलिए हमें केवल बातों सेही काम नही लेना चाहिए कि हम यहां असैम्बली में बैठकर पड़ौसी स्टेट को धमकियां दें, इससे फायदा नहीं हो सकता । हमें प्यार से काम लेना चाहिए और अगर कोई पड़ोसी प्रान्त भाई चारे के तरीके से नही मानता तो हमें केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिए । इसके अलावा मैं एक बात और कहना

चाहता हूं वह यह है कि जो नहर हमने बनानी है यदि वह उतनी ही चौड़ी रही तो उसमें कट होते रहे गे इसलिए हमें उसके बराबर की जमीन भी लेनी चाहिए ताकि लोग कट न करें । कई भाइयों ने डाउट्स प्रकट किए हैं, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई होगी कि पंजाब सरकार जानबूझ कर इसमें देर करना चाहती है यदि पंजाब सरकार देर करना चाहती है तो यह बात अच्छी नहीं है । हमें यह बात से टर कें—नोटिस में लानी चाहिए वरना इस फैसले का हमें कुछ फायदा नहीं होगा । अगर वे जानबूझ कर देर करना चाहते हैं तो अबतो एमरजैन्सी लगी हुई है जबकि दूसरे सारे कानून स्थगति करके सरकार दूसरे ढंग से काम चला सकती है । तो इसमें भीएमरजैसी का इस्तेमाल कर जमीन एक्वायर कूरके इस काम को बहुत जल्दी करवा के दे सकते हैं । आज एमरजैंसी के दिनों में केन्द्र सरकार को वे अधिकार मिले हुए हैं कि कोई भी प्रान्त या व्यक्ति किसी ठीक काम में देर नहीं कर सकता । इसलिए इस काम को केन्द्र सरकार जल्दी कर सकती है । यदि यह पानी न आया और एक दो साल और देर हो गयी तो उस से जो नुक्सान होगा उसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं । लगातार हमें 6 साल से नुक्सान हुआ है क्योंकि फैसला नहीं हुआ था । अब क्योंकि फैसला हो चुका हे इसलिए जितना भी पानी हमें मिला है उसको लाने में देर नही होनी चाहिए । वह पानी जब खेतों में पहुंचेगा तो उससे हमें बेशुमार फायदा पहुंच सकता है । इसलिए राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक मिनट भी देर न करे । आप अगर बातें करके ही चुप बैठ गए तो उससे

लाभ होने वाला नही है । जिन भाइयों ने चौलेंज किये हैं कि हम पंजाब गे साथ ये करेंगे वो करे गे वे भाई, यह तो पता नहीं वैसा कर पायेंगे कि नहीं लेकिन पंजाब वाले जरूर देर करेंगे इसलिए मैं समझता हूं कि चौलेंज देने का कोई फायदा नहीं है । हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और भाईचारेके तरीके से काम निकालना चाहिए । परसों लैड सीलिंग पर जब बहस चली थी तो उसमें एश्योर्ड इरिगेटिड लैड की या चाही लैड की चर्चा थी और जितने रूल्ज बने है उन में भी सिचित भूमि की सबसे बड़ी चर्चा है लेकिन मैं पूछना चाहता हू कि सिचित भूमि है कहां? अगर कहीं भूमि को नहर का एक पानी मिल जाता है तो उसको नहरी लिख देते हैं और अगर ट्यूबवैल का एक पानी लगता है तो उसको चाही बना देते हैं लेकिन एशोयर्ड इरिगेशन के रूल्ज से जमीन को चाही या नहरी समझ कर कुछ फसलों की शर्त लगाकर जमीन को एशोयर्ड इरिगेटिड समझा गया तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अन्याय होगा ।

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज, यह रेजोल्यूशन के स्कोप से बाहर है आप रेजोल्यूशन के अन्दर बोलें ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब हम जमीन को पूरा पानी दे सकेंगे या यह समझेंगे कि जमीन को हमने पूरा पानी दे दिया है तभी उसको एशोयर्ड इरिगेटिड कह सकेंगे नही तो पानी देने से उसे सिंचित नहीं कह सकते क्योंकि उसमें पूरी पैदावार नही होगी और साथ

ही किसान और प्रान्त को लाभ भी नही होगा । इसलिए हमने एशोयर्ड इरिगेशन बनानी है । अगर हमने एशोयर्ड इरिगेशन बनानी है और पूरा पानी देना है. ताकि दोनों फसले पूरी हों तो यह जरूरी है कि इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाया जाए और उदाकी जो आगे चौनल हैं वह तो बना ही ली हैं उनमें जो थोड़ी बहुत कमी मालूम होती है उसका भी हम पूरा करे । वैस्ट्रन जमुना कैनाल में भी पानी की बहुत कमी है मैं समझता हूं कि इसमे भी पानी की सहायता मिलेगी इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि रावी व्यास का पानी जल्दी हरियाणा की सर जमीन पर लाया जाये । केवल हम इस भरोसे पर न रहें कि पहाड से पानी आ गया तो मिल गया नही तो सूखे ही बैठे रहें । फर भी अगर गिरदावरी में नहरी लिखा जाए तो उससे लाभ नहीं होगा बल्कि नुक्सान होगा । इसलिए जहां नहर का एक पानी भी नहीं मिलता तो उस सूरत में किसान कोई और साधन सोचकर सिंचाई करें जिससे फसल तैयार हो सके । इसलिए मैं 'निवेदन करूंगा कि हमें नहर के पूरे पानी की बहुत आवश्य– कता है, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें और इस पानी को लाने के लिए पूरा प्रयत्न करें । जब तक इस पानी को लाने में कामयाबी नही हो जाती तब तक चौन से न बैठें, बाकी तरफ से बेशक ध्यान हटालें । 209 किलोमीटर लम्बी नहर जो है यह आधी पंजाब में गुजरनी है और आधी हरियाणा के रकबे में है । हरियाणा के एरिया में भी आज से बनानी शुरू करेंगे तब भी बहूत मुश्किल से पूरी कर पायेंगे । पंजाब में तो बहुत मारी काम है, पहले जमीन एक्वायर

होनी है फिर उसकी खुदाई होनी है, तो यह छोटा काम नही है इसलिए दिन रात दिमाग में रखकर यह काम पूरा हो सकेगा और जब तक यह पूरा नहीं हो जाता मुख्य मन्त्री इस बात का पक्का इरादा बना लें कि बेचौन से नहीं बैठेंगे और कोई ढील नहीं दिखायेंगे नहीं तो मैं समझता हूं कि भाषणों से कोई बात नही बनेगी क्योंकि हमने पंजाब से कोई मोर्चा नहीं लगाना । कई भाइयों ने कहा कि केन्द्र मेँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वे खुदाई में सहायता करेंगे । वे पानी के बंटवारे में जो कुछ कर सकते थे वह सहायता उन्होंने की है । यह ठीक है कि हमें अभी भी कम हिस्सा मिला है लेकिन फिर भी जितना मिला है वह उनकी वजह से मिला है और उनकी हिम्मत से यह जल्दी फैसला हो पाया है । यह बडी भारी मदद है । उनकी इस मदद को हम न भुला कर इस बात में उन्हें न खीचें क्योंकि वे पंजाब के रक्षा मन्त्री भी उसने हैं जितने कि हरियाणा के । एक हरियाणवी होने के नाते से आपकी जो नियमित रूप से वे सहायता कर सकते हैं वे कर रहे है और करेंगे और करनी भी चाहिए । इसलिए उनका भी सहयोग आप लें और केन्द्रीय सरकार में उनके असर और रसूख को जितना आप इस्तेमाल कर सकते है उतना करें और इसका फैसला बहुत जल्दी कराएं ताकि अलाइनमैंट करने का जमीन ऐक्कयर करने का और खुदाई का काम बहूत जल्दी मुकम्मल हो । स्पीकर साहब, सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह न समझे कि यहां अलग अलग पार्टियां हैं इस काम में सभी पार्टियां एक हैं, सारी जनता एक है, सारी जनता की

आवाज एक है बल्कि मुख्य मन्त्री जी यह समझे कि सारा हरियाणा इस काम के लिए उनके साथ है । जैसी भी आवाज वे उठाना चाहेंगे लोग वही आवाज उठाएंगे लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें ढील न आने दें । इन शब्दोंके साथ इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करतेहुए मैं मु ख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ड्ह काम को बहुत जल्दी सम्पन्न कराने का प्रयत्न करें और मैं आशा करता हूं कि वह सदस्यों की शंकाओं को सच्ची नही होने देंगे ।

राव बंसी सिह (अटेली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज चौधरी मइहर चन्द जी ने जो प्रस्ताव सतलुज और व्यास नहर के लिंक का रखा वह बहुत महत्वपूण' है । इसके लिए जहां मैं चौधरी मेहर चन्द जी का शुक्रिया अदा करता हूं वहां में बाबू गुलाब सिंह जैन जी का भी ैउक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि आज हरियाण को किस रैजोल्यूशन की आवश्यकता है, हरियाणा की जनता क्या चीज महसूस कर रही हद और अपने रैजोल्यूशन को विदड्रा किया । अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले जो व्यक्ति बोले उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की है । इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ पांच मिनट के लिए आपके सामने अपने विचार रखूंगा । सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज जो हरियाणा के सामने सतलुज और ब्यास के पानी का फैसला आया वह आज से 6 साल पहले हो सकता था लेकिन किन्हीं हालात की वजह से' वह फैसला नही हो सका । इस

फैसले से हमें जो 50 परसैंट का आधा शेयर मिला, मैं समझता हूं कि यह हमें पूरा शेयर नहीं मिला लेकिन फिरभी मैं प्रधान मन्त्री जी, रक्षा मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी और मुख्य मन्त्री श्री गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इनकी कोशिशों से यह फैसला जल्दी हौ पाया है । अब रह गई यह बात, अध्यक्ष महोदय, कि जो फैसला आज हमारे सामने आया है वह इम्पलीमैंट कितने दिनों के अन्दर होता है । मै इस बात को सरकार की कोताही नहीं बताऊंगा कि जो पानी आना है

उस पानी को पहुंचाने के लिए सरकार ने सबसे पहले हरियाणा के अन्दर काम स्टार्ट किया । यह अच्छा काम था । वह नहर जो इन्होंने शुरू की वह है जिसे इन्होंने उन इलाकों के अन्दर पहुंचाया, उन इलाकों के जजबात को समझ कर जहां की धरती सदियों से प्यासी सुनते थे, वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था । उन लोगों की सूझ चौधरी बंसी लाल के शासन के अन्दर ली गई । इस प्रदेश के अन्दर दो ही नहरें थीं एक वैस्टर्न जमुना और दूसरी भाखडा कैनाल और इन दोनों नहरों का पानी करनाल, रोहतक और जींद के कुछ हिस्सों तक जाता था । गुडगावां महेन्द्रगढ़, भिवानी का जिला सारा, रोहतक का साल्हावास, ये ऐसे इलाके थे जिनकी प्यास आज तक नही बुझ सकी थी । चौधरी बंसी लाल ने उस इलाके की तरफ देखा, उन लोगों के इतिहास के ऊपर नजर डाली । इतिहास के अन्दर उन लोगों को हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हिस्सा मिला । सबसे पहले

हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए सन 1857 का गदर हुआ । उसमें वहां के लोगों ने राव तुला राम की अध्यक्षता में बहुत सी कुर्बानियां कीं । देश स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता के बाद दो लड़ाइयां हुईं, एक चीन के साथ और दूसरी पाकिस्तान के साथ और उस रेगिस्तानी इलाके ने जहां आज पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वीर चक्र और महावीर चक्र प्राप्त किए । उन लोगों की तरफ ध्यान गया चौधरी बंसी लाल जी का । उन्होंने महसूस किया कि उनको भी पानी प्राप्त करने का हक है । इसीलिए जवाहरलाल नेहरु कैनाल स्कीम बनी लेकिन इस जवाहरलाल नेहरू कैनाल के जरिए पानी तभी पहुंच सकता है जब सतलुज व्यास लिंक चौनल को पंजाब सरकार बनाए या हरियाणा सरकार बनाए । अध्यक्ष महोदय, यह उस इलाके की बदकिस्मती रही कि वहां के रहने वाले लोग आज तक अपनी प्यास नहीं बुझा सके । जब सरदार प्रताप सिंह कैरों की सरकार थी तो उस समय भी उस इलाके के लोगों ने पानी ले जाने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्यवश वे पानी नहीं ले जा सके । उसका उन्हें बहुत बड़ा नुक्सान उठाना पड़ा । राव वीरेन्द्र सिंह जी डिसमिस हुए । उन्होंने चाहा था कि सोहना लिफ्ट स्कीम बना करके उस इलाके में पानी ले जाया जाए लेकिन वे पानी नहीं ले जा सके । वह काम अधूरा रह गया था । आज चौधरी बंसी लाल जी की देनको वह इलाका भूल नहीं सकता । वे लोग गुप्ताजी को भी नहीं भूल सकते क्योंकि जो आदमी लग्न से काम कर रहा है उसे कैसे भूला जा सकता है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज जो फीलिंग्ज यहां ऐक्सप्रैस की गई वे फीलिंग्ज सब

भाइयों की है, सारे हरियाणा के बच्चे–बच्चे की फिलिंग्ज हैं । जिस तरह से भाखडा और चण्डीगढ के फैसले के समय एक–एक बच्चे के अन्दर जोश आ गया था, आज वही वक्त है । उसी तरह का जोश आज लोगों में आ रहा है । वे पहते हैं कि पचास परसैन्ट हिस्सा पानी का जो हमें मिला है वह जल्दी से जल्दी हरियाणा की धरती के अन्दर पहुंचाया जाए । यदि हमारी सरकार ने गौर नहीं किया तो फिर हरियाणा के रहने वाले बच्चे–बच्चे के अन्दर, जवान और बूढ़े के अन्दर एक जोश उत्पन्न हो सकता है अपना हक मांगने का । हरियाणवी ने हमेशा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा का बच्चा–बच्चा सरकार के साथ है । हरियाणा का हर एम० एल० ए० चाहे वह अपोजिशन का है या कांग्रेस का है, मुख्य मन्त्री जी के साथ है । मैं यह नहीं कहता कि पंजाब के भाई हमारे शत्रु हैं । हम तो दो भाई थे और अब दो हिस्से के अन्दर तकसीम हो गए हैं । आज हम बैठ करके बहुत जरुरी ही इस मसले को हल कर सकते हैं । आज इस ऐमरजैन्सी के अन्दर 20 प्वायट प्रोग्राम लागू होंके के बाद, मैं समक्षता हूं ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे इस मामले में अधिक से अधिक मदद करेंगे । मै समझता हूं कि वे बहुत अच्छे मुख्य मन्त्री है और वे इस बात को कहने का मौका नहीं देंगे कि इस काम में पंजाब की वजह से डिले हो रही है । अन्त में, स्पीकर साहब, मैं यही रिक्वैस्ट करूंगा कि हमारी फीलिंग्ज को हमारे मुख्य मन्त्री जी

ज्ञानी जैल सिंह तुक पहुंचाए और अगर कोई जरूरत पडे तो प्रधान मन्त्री तक भी पहुंचाए ।

श्री के० एन० गुलाटी (फरीदाबाद) : आनरेबल स्पीकर साहब, मैं इस रैजोल्यूशन पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बड़ा अच्छा प्रस्ताव है जो आज सदन के सामने आंया है । स्पीकर साहब, यह पानी का मसला हरियाणा के लोगों की जिन्दगी और मौत की सवाल थी और है । जब यहं खबरें हम लोगों ने सुनी कि चौधरी बंसी लाल–और मुख्य्र मन्त्री श्री बनारसी दास गुप्त की कोशिश से प्रधान मन्त्री जी ने रावी ब्यास के पानी का सला कर दिया है और उसमें से हमें पूरा हिस्सा मिलेगा तो हरियाणा के लोगों के अन्दर एक खुशी की लहर दौड़ गई । हरियाणा के बच्चे–बच्चे ने इस बात की खुशी मनायी कि हमारा डयेशेयर तो कुछ मिला। इस पानी के मिल जाने से हमारी कई तकलीफे टूर होंगी क्योकि किसानो की जिन्दगी का दारीमदार तो पानी पर ही है । यह हर इन्सान की जिन्दगी और मौत का सवाल है अगर पानी मिलेगा तो हम अनाज ज्यादा पैदा करेंगे बिजली ज्यादा पैदा करेगे। बिजली ज्यादा पैदा होगी तो फैक्टरीज में प्रोडक्शन ज्यादा होगी । शहर में रहने वाले लोगों को भी इससे फायदा होगा । जहां हमें यह खुशी हुई थी कि रावी व्यास का पानी मिलेगा वहां साथ ही यह गमी भी नजर आने लगी है कि यह इतना जल्दी नहीं मिलेगा । हरियाणा के लोग अभी तक पानी की कमी होंते हुएं भी बहुत तेजी के साय आगे बड़े है और पंजाब से

कभी किसी मामले में पीछें नहीं रहे । हमारी हर तरह से सैन्टर ने मदद की है । जहां आज हम यह खुशी मना रहे हैं वहां आज हमे यह दुखभरी बात भी सुनने को मिली जिसके कारण से यह रैजल्यूशंन यहां हाउस में आया मैं तो यह समझता हूं कि वह खुशी की लहर शायद कुछ देर से मिले क्योंकि पंजाब वाले भाई कुछ गड़बड़ करना चाहते है । तो हमें दु:ख हुआ लेकिन स्पीकर साहब मैं इस बात को बड़े मीठे शब्दो में आपके द्वारा पंजाब सरकार और पंजाब के भाइयों तक पहुचाना चाहता हूं कि हरियाणा ने हर बात को बड़े मीठे तरीके से सुलझाया है । खुशी कें माहौल – में यह फैसला हुआ है । अगर किसी की मंगनी हो जाये और विवाह न हो तो यह बड़ी गलत बात होती है मैं तो कहता हूं कि जब मंगनी हुई है तो विवाह हो कर ही रहेगा पंजाब की पहलें जैसी मनमानी नहीं चलेगी। हम तो चाहते हैं कि सारी बाते प्यार और श्रद्धा से हों मैं चाहती हू कि यह काम जल्दी–से जल्दी 'कम्पलीट होनो चाहिए । अगर हरियाणा खुशहाल प्रदेश, है तो हमारा पडोसी प्रदेश पंजाब भी खुशहाल होगा । प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल बन सकेगा । तो इस बीत में पंजाब वाले भाइयों को अड़चन नहीं डालनी चाहिए । उनको तो हमारी इस बात में मदद करनी चाहिए। यह केवल हमारे प्रदेश का सवाल नही है, इसमे तो सारे देश के भले का सवाल हैं । मैं मुख्य मन्त्री जो को वैह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां भी हैमें लें जाना चाहें हमे जौने के लिए तैयार हैं मैं ही नही इस सदन के सभी एम ०एल०ए ० आपके साथ हैं । हमारे महबूब

रहनुमा डिफेन्स मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल चाहे जहां कहीं भी हमें ले जायें है उनके साथ हैं । हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्री भी हरियाणा प्रदेश को बहुत तेजी के साथ आगे बढाना चाहते है वे दिन और रात 24 घन्टें प्रदेश की भलाई के काम कर रहे है । हरियाणा की जनती उनके साथ है । उनकी आवाज पर जहा वे इकट्ठा होना चाहते हैं वहां जाने को तैयार हैं जो भी बात करना चाहें, हम सब उनके साथ है ।

स्पीकर साहब, मै अपनी जगह लेने से पहले यह बात कहूंगा कि अगर पंजाब सरकार खुशी से यह मानती है तो बड़ी अच्छी बात है । अगर वे हमारा इम्तहान लेना चाहते है तो वह भी हम देने के लिए तैयार हैं । मैं एक शेर कह कर अपनी जगह लेता हूं –

मिटा दे अपनी हस्ती को तुझे गर मुरतवी चाहिए

कि बाना खाक मैं मिल कर गुलें गुलजार हौता है । ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (महम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन– के सामने लिंक' कैनाल का प्रस्ताव आया है, यह बडा अहम प्रस्ताव है– । जहां सदन के मेरे दूसरे साथियों ने चौधरी मेहर चन्द को इस अहम प्रस्ताव को लानेके लिए बधाई दी है, मैं भी उनको बधाई देता हूं और उनका बड़ा मश्कूर हूं कि वे इस प्रताव को यहां सदन में लाये । इस प्रस्ताव को ला कर उन्होने हरियाणा के किसानों के अन्दर जान डाली है क्योंकि

हरियाणा को किसान कई सालों से पानी की कमी की वजह से ना–उम्मीद हो बैठा था उसको इस प्रस्ताव के आने से आशा बन्धेगी । मैं सरकार का, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ध्यान दिलाने चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट करुके हमारे किसानों की ना–उम्मीदी को उम्मीद ये बदले हरियाणा जो कई सालों से पानी के मामले में ना–उम्मीद हो बैठा भी उसको जल्दी से फिर उम्मीद में बदला जाये । अब तो इस पानी के मिलने के बाद लोग यह आशा लगाये बैठे हैकि यह जल्दी से जल्दी मिले ।

जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि चौधरी बंसी लाल की हर उम्मीद को, हर उनके अधूरे रहे हुए कामों को पूरा किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि गुह भी चौधरी बंसी लाल जी की ही इच्छा थी कि हरियाणा के अन्दर इस लिंक कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये और हरियाणा के किसानो को पानी दिया जाये । तो मैं उम्मीद रखता हूं कि हरियाणा सरकार इस लिंक को जल्दी से जल्दी पुरा करेगी । चौधरी बंसी साल और किसानों की उम्मीदों को भी पूरा करेगी । मैं किसान होने के नाते यहां सदन ने यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हर तरह का सहयोग देने के लिऐ तैयार है । हरियाणा सरकार, यदि इस प्रस्ताव के अन्दर जो टाईम दिया गया है जैंसा कि मेरे माननीय साथी ने जून सन 1977 तक कहा है इस लिंक को पूरा करदिया जायेगा, अगर उस समय तक यह लिंक

पूरा होगा तो हरियाणा का श्रमिक किसान जल्दी से जल्दी अपनी कडी मेहनत के सांप हरियाणा के अन्दर हरी क्रान्ति पैदा कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार दिसम्बर तक इस लिंक को पूरा करने मे सफल होगी। हरियाणा की प्यासी भूमि है यह सभी भाईयो को पता है कि यह लिंक सन 1970 तक पूरा होना चाहिए था लेकिन सन 1970 से 1976 तक भी पूरा नहीं हुआ । अब तक इस पर कोई भी काम नही हुआ है । अगर यह सन 1977 के बाद भी पूरा नहीं हो सकता तो बहुत ही ज्यादा दुख होगा । मैं इस बात पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं । जो हक थोड़ा बहुत हमें मिला है, यह बड़ी खुशी की बात है । अब सवाल इस बात का नहीं है कि कितना हक मिला है । अब तो सवाल इस बात का है कि जो कुछ हक मिला है उसको जल्दी से जल्दी हरियाणाके किसानों तक पहुंचाया जाये । मैं अपना स्थान लेने से पहले अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हरियाणा सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि यह जो लिंक है यह शीघ्र से शीघ्र पूरा हो ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो प्रस्ताव आज सदन के विचाराधीन है उसका हरियाणा के लिए बड़ा भारी महत्व है और यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि रावी व्यास के फालतू पानी में जो हिस्सा हरियाणा को मिला है उसका प्रयोग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक प्रस्तावित लिंक कैनाल समय पर बन कर तैयार नहीं हो जाती । इस प्रस्ताव की चर्चा करते हुए मेरे कई सम्मानित साथियों

ने यह आशंका प्रकट की हैकि शायद इसलिए कैनाल के बनाने में देरी हो जाए । यह आशंका सही है । अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश का एक–एक व्यक्ति मुंह बाये बाट देख रहा है कि कब रावी–व्यास का पानी आए और कब हमें सिंचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध हो । इस विषय पर मैं आगे चर्चा करने से पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि बतलाना चाहता हूं कि यह पानी कैसा है, कैसे यह उपलब्ध हुआ और किस सिद्धान्त पर इस पानी का बंटवारा हुआ । अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आज से कई साल पहले भारत सरकार की पाकिस्तान के साथ एक इन्डस वाटर ट्रीटी हुई और उस सन्धि के अन्तर्गत रावी– व्यास का सरप्लस पानी जो बह कर पाकिस्तान में जाता था वह भारत सरकार को मिला । भारत सरकार को इस पानी के बदले 110 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर पाकिस्तान को देना पड़ा और 1970 से इस पानी पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार छोड़ दिया । इन सब बातों को ध्यान में रख ते हुए भारत सरकार ने इस प्रकार की एक योजना बनाई कि 1970 तक इस पानी को हिन्दुस्तान में लाया जाए और इससे फायदा उठाया जाए । अध्यक्ष महोदय, ब्वास प्रोजैक्ट की जो परियोजना तैयार की गई थी उसके लिए यह लक्ष्य तैयार किया गया था कि 1970 तक यह प्रोजेक्ट बन कर तैयार हो जाएगा । परन्तु शायद आपने भी उस प्रोजेक्ट के स्थान को जाकर देखा हो और मैने भी देखा है कि यह प्रोजेक्ट, यह काम बहुत ही मुश्किल है और मुश्किल ही नहीं है बल्कि जान जोखिम का काम है । जिस प्रकार एक सिपाही मोर्चे पर लड़ते हुए खतरे का सामना

करता है इसी प्रकार का यह काम है । वहां काम करने वाले मजदूर और काम करने वाले इंजिनियरों के सामने हर वक्त खतरा मुंह बाये खड़ा रहता है । अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक रूप से उस पानी को भारत में लाने के लिए कोई रास्ता नहीं है । बीच में पहाड़ है और बहुत ऊंचे पहाड़ हैं । उन पहाडो मे तीन सुरंगें बनाई और उन सुरंगों के द्वारा पाकिस्तान से यह पानी भारत में लाना है । सुरंग तैयार करने का काम इतना मुश्किल काम है कि जो आसानी से बताया नहीं जा सकता कि कितने समय में काम पूरा होगा और कब तक पूरा हो जाएगा । कई बार यह होता है कि पहाड़ का स्ट्रेटा इतना कमजोर होता है कि पहाड़ का पहाड़ टूट कर गिर जाता है और उससे मजदूर और इजीनियर मौत के शिकार हो जाते हैं । एक दो बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई भी हैं । इसलिए यह प्रोजेक्ट 1970 तक जैसा कि अनुमान लगाया था, पूरा नहीं हुआ । पता चला है और जैसा कि इजीनियर्ज ने ऐलान किया है और आज से कुछ समय पहले अखबारों में भी छपा था कि जुलाई, 1977 में यह व्यास प्रोजेक्ट बन कर तैयार हो जाएगा और प्रोजेक्ट तैयार होते हो पानी उपलब्ध हो जाएगा । तो हमारे मैम्बर साहिबान का यह कहना बिल्कुल सही है कि जब तक यह पानी उपलब्ध हो तब तक हमारी लिंक कैनाल बन कर तैयार हो जानी चाहिए क्योंकि जब तक लिंक कैनाल बन कर तैयार नहीं होगी हम अपने हिस्से के पानी का लाभ नही उठा पाएंगे । मैं एक बात सदन को बतलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि जब तक 1– । कैनाल नही बनती हम पूरे के पूरे पानी को जाया करते

रहेंगे । हम कुछ पानी का प्रयोग कर पायेंगे । आप जानते है कि भाखडा मेन कैनाल की जो क्षमता है वह कुछ अधिक है और पानी कम बहता है । उसकी क्षमता का, उसकी कैपेसिटी का लाभ उठाते हुए कुछ पानी को एग्जिसटिंग चौनल से हरियाणा में कैरी कर सकते हैं लेकिन पूरे पानी का लाभ हम तभी उठा सकेंगे जब कि हमारी लिंक कैनाल बन कर तैयार हो जाएगी । इस सन्दर्भ में मैं एक बात बतलाना चाहता हूं क्योंकि इस बात की चर्चा है कि हमें हमारा हिस्सा कम मिला । स्पीकर साहब, 1921 से 1945 तक कुल पानी की उस वक्त जो कैलकुलेशन की गई उस कैलकुलेशन के आधार पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत सरकार को टोटल पानी जो मिला वह था 15.85 मिलियन एकड़ फीट । इस 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी का बंटबारा भारत सरकार ने फौरन ही कर दिया । यह पानी राजस्थान अर्स्ट व्हाइल पंजाब,पैप्सू और जम्मू तया कश्मीर को दिया गया और भारत सरकार ने पानी के बंटवारे के समय जो सिद्धान्त अपनाया, मैं जहां तक समझता हूं वह सिद्धान्त यह था कि जहां जिस प्रदेश को पानी की अधिक आवश्यकता है, जो इलाका ज्यादा सूखाग्रस्त है, जो कहत का शिकार होता है उस इलाके को ज्यादा पानी दिया जाए और यही कारण है कि 15. 85 मिलियन एकड़ फीट पानी में से आठ मिलियन एकड़ फीट पानी यानी आधे से अधिक पानी राजस्थान को दिया गया और इसलिए दिया गया कि वह इलाका सूखाग्रस्त था, पानी की वहां ज्यादा आवश्यकता थी । अध्यक्ष महोदय, आप यह भी जानते हैं कि कुछ समय बाद पैप्सू, पंजाब के अन्दर मर्ज

हो गया और पंजाब और पैप्सू दोनों का हिस्सा 72 मिलियन एकड़ फीट बन गया और फिर आगे चलकर 1986 में स्टेट का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा प्रदेश अलग बना । हरियाणा प्रदेश थे 72 मिलियन एकड़ फीट पानी में से अपने हिस्से के पानी की मांग की और मांग भी ज्यादा पानी की की और मैं समझता हूं कि उस मांग में इन्साफ था, न्याय था और सिद्धान्त भी था क्योंकि भारत सरकार ने जो सिद्धान्त अपनाया और जिस सिद्धान्त पर राजस्थान को आधे से अधिक पानी दिया गया वही सिद्धान्त हरियाणा प्रदेश के साथ लागू होता है क्यौंकि आप. जानते हैं और मैं समझता हूं कि पडोसी राज्य पंजाब के भाई इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि सिंचाई के साधन हमसे कही अधिक उनके पास उपलब्ध हैं । उनके यहां भूमिगत पानी हमारे यहां से ज्यादा मिकदार में उपलब्ध है । जहां हमारे यहां वाटर अलाउंस 66 परसेन्ट है वहां पंजाब में 80 परसैन्ट है इतना भारी अन्तर सिंचाई के साधनो में है और इसी आधार पर भारत सरकार से यह मांग की गई कि हरियाणा प्रदेंश को ज्यादा हिस्सा इस पानी में रखा जाए वह बात काफी अर्से तक चलती रही । मुझे इसबात को दुहराने की आवश्यकता नहीं है आखिर फैसला आज से कुछ दिन पहले हमारी प्रधान मन्त्री जी की कृपा से, उनकी मेहरबानी के भारत सरकारने किया । जिन भाईयों ने यह बात कही कि जितना हिस्सा हमें मिलना चाहिए था उतना–हिस्सा नही जिस सिद्धान्त है उनकी इसबात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि जितना पानी हमें मिलना चाहिए था जिस सिद्धान्त की बात मैंने कही उस सिद्धान्त के आधार पर इस पानी 'के

बटवारे में उतना पानी नहीं मिला लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रधान मन्त्री जी का हृदय से आभारी हूं और मैं ही नही बल्कि हरियाणा को एक एक बच्चा आभारी है (थम्पिग) कि कम से कम फैसना तो हुआ । जो फैसला हो ही नही रहा था वह उनकी कृपा से फैसला हुआ और मगर वह फैसला आज से कई गाल पहले हो जाता तो हमको उसका ज्यादा फायदा होता।

कई भाइयो ने इस फैसले की चर्चा करते हुए रक्षा मन्त्री चौधरी बंसी लाल का गम लिया मै यह कहना चाहता है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि चौधरी बंसी लाल के नेतृत्व में उनके मुख्य मंत्रित्व काल मे हरियाणा प्रदेश का एक प्रकार से कायाकल्प हुआ है बल्कि मैं तो यह कहूगा कि यह उनकी दूरदर्शिता का एक बड़ा स्पष्ट प्रमाण है कि उन्होंने इस पानी के बंटवारे से पहले इतना ईफाम्ट्रक्चर तैयार कर दिया था कि अगर आज भी हमें पानी मिल जाए या एक मात्र पहले भी मिल जाता तो उस सारे पानी का प्रयोग कर सकते थे । आपको याद होगा कि जब पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन हुआ तो कायदे के हिसाब से बिजली हमें अधिक मिलनी चाहिए थी – लेकिने हमारे पास अपने हिस्से की बिजली कंज्युम करने के साधन नही थे । ट्रासमीशन लाइन कम थी और न बिजली को लाने के साधन उपलब्ध थे इसलिए बिजली से हमें कम हिस्सा गया । अगर इस. पानी के प्रयोग के लिए साधन उपलब्ध न हाते तो हमें पानी भी कम मिलता । हमारे भाई कहते है कि यह पानी कहां प्रयोग करेंगे लेकिन मैं चौधरी बंसी

लाल की सराहना करता हूं कि उन्होने बड़ी दूर अन्देशी के साथ काम लिया और जो भी सूखाग्रस्त इलाके हैं जहां उनके राहत पहुंचाई, वहां इस पानी को प्रयोग करने के लिए साधन भी पैदा किए लेकिन ईस पानी के बंटवारे के फैसले में चौधरी बसी लाल जी को घसीटा जाए यह कोई उचित बाते नही है 1 चौधरी वैसी लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे और आज वे भारत सरकार के रक्षा मन्त्री हैं उनके लिये तो हरियाणा प्रदेश कैसे ही है जैसे कि पंजाब प्रदेश और दूसरे कय प्रदेश । कैबिनिट के अन्दर जब यह मामला आया तो उन्हौंने इस फेसले का समर्थन यह समझ कर नही किया कि वे हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री ये बल्कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की इस मांगे को उचित समझते हुए इस का समर्थन किया मैं तो यह कहूंगा कि यह फैसला हमारी प्रधान–मन्त्री जी का है । प्रधान मन्त्री जी की कृपा से यह हुआ है और उनके आशीर्वाद से हुआ है । उसके बाद अब इस पानी को यहां लाने की बातें है । पानी का बंटवारा होने के बाद मुझे भी इस बात का फिकर हुआ कि जल्द से जल्द इस लिंक कैनाल को तैयार किया जाए और जैसे मैने पहले भी इस सदन मे बताया था कि जिस हिसाब से हमने इस प्रोपोजड कैनाल की एलाइनमैंट करके भेजा है उस हिसाब से इस की लम्बाई 209 किलोमीटर बनती है जिसमे से 103 किलोमीटर पंजाब में बननी है और 106 किलो मीटर हरियाणा बननी है।

चौधरी शिव राम वर्मा : इस कीं चौडाई कितनी है?

श्री बिनारसी दास गुप्त : फुटों मै तो मुझे 'मालूमें नहीं लेकिन उसकी कैपेसिटी 9000 क्यूसिक्स तक की है । तो इसे प्रकार मैंने इस बात पर विचार किया कि लिंक कैनाल का कामे जल्दी शुरु होना चाहिये और वह जल्द–से जल्द बन करे तैयार होंनी चाहिये लेकिन तब तक – वह बन नही सकती, इसका काम शुरू नहीं हो सकता, जब तक कि पंजाब प्रदेश का सहयोग हमें न मिले। मैंने पंजाब प्रदेश कैं मुख्यमन्त्री ज्ञानी जैल सिंह जी से बात की है । पंजाब और हरियाणा प्रदेश' मैं कोई फर्क नही है । मेरे कुछ भाइयों ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कुछ सख्त बातें कहीं, मैं नहीं चाहता और मैं पसन्द नहीं करता कि ऐसी बातें हमारे पड़ोसी प्रदेश के बारे में तथा उसके सम्मानित मुख्य मन्त्री के बारे मैं कही जाएं । पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही राष्ट्र के अंग हैं 1 एक ही राष्ट्र के अंग ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ऐक ही शरीर थे । आज पंजाब के हितों केविरुद्ध कोई बात हम कहे तो हमारे लियें शोभा की बात नही है । पंजाब के भाई अगर हरियाणा के हितों के खिलाफ कहें, वह उनके लिये मुनासिब नहीं, उचित बात नहींहै, हम दोनों पड़ोसी प्रदेश हैं । यह बात दूसरी है कि पडोसियौं में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में भो झगड़े हो जाते हैं । दो भाई जब अलग हो जाते हैं तो उनमें जमीन के बंटवारे पर या किसी दूसरी चीज पर झगड़ा हो जाता है, घर की सम्पति कैं बटवारे पर झगड़ा हो जातां है, यह बातें स्वाभाविक हैं । इस प्रकार यह भी एक झगड़ा था जिसका फैसला अभी पिछले दिनों हुआ । जब तक पंजाब वालों का सहयोग हमें नहीं मिलता

'तब तक हम कैनाल का काम शुरू नही हो सकता । इसलिये में ज्ञानी जी से मित्रा, उन से प्रार्थना की, उनके दफतर में भी गया, उन्होंने सहर्ष कहा कि यह काम होना चाहिये –(तालियां) और इस–काम को हम शुरू करेंगे ` इस के बाद हम दोनों ने यह निश्चय किया कि दोनों प्रेदेशों के इंजीनियर्ज हमारे साथ बैठकर इस नहर की एलाइनमैंट को देख लें अपर कोई एलाइनमैंट में तबदीली करनी हो तो कर लें और इस बात का फैसला कर ले कि पंजाब के हिस्से में इस कैनाल को पंजाब के इंजीनिबर्ज ने बनाना है या हुमारे इंजीनियर्ज ने बनाना है । मैंने दोनों बातों पर सहमति प्रकट की । अगर – पंजाब के इंजीनियर्ज बनाए तो बड़ी खुशी की बात है इस कैनाल पर जितना पैसा खर्च होना है – वह हमारे से जमा करवा लो और अगर हमारे इजीनियर्ज ने बनाना है तो हमें जमीन एक्वायर करके दे दो हम बनालेंगे । दोनों तरह की बातें, दोनों तरह के विकल्प, दोनों तरह के आल्टरनेटिव मैंने पेश किये और उन्होंने म्उझे कहा कि ठीक है। कोई तारीख रख ले उस तारीख को बैठकर बात करेंगे । इस के बाद मैंने दौ बार प्रार्थना की, चिट्ठी भी लिखी लेकिन वह तारीख अब–तक तय नहींहो पाई । मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता । हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां हों, कुछ व्यवस्थाएं हौ लेकिन विलम्ब हो रही है–उसको देखकर मैम्बर साहबान के ह्रदय में आशंकाएं पैदा होनी स्वाभाविक ही है । मैं इसे कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि जैसा कि चौधरी रिजक राम जी ने कहा है और मैं उनकी बात से सहमत हुं कि यह लिंक कैनाल हरियाणा प्रदेश की लाईफ

लाइन है, यह हमारी जिन्दगी का सवाल है, हमारी खुशहाली का सवाल है ।

स्पीकर साहब, आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित हैं । हरियाणा प्रदेश का किसान कितना मेहनती है लेकिन सिंचाई के साधन न होने के कारण उसकी मेहनत का पूरा फायदा उसे, देश को और प्रदेश को नहीं मिल पाता है । इसलिये जल्द से जल्द इस पानी को यहां पहुंचना चाहिये और इसके लिये हर व्यक्ति का चिन्तित होना एक स्वाभाविक बात है । इस पानी से हमें कितना फायदा होगा इस के बारे में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हू । मैने 3.5 मिलियन एकड़ फीट की गणना रखी थी, उसके हिसाब से हमारा हिस्सा बढ़ जाता है । जहां हमारा बढ्ता है वहां पंजाब का भी बनता है. वह कैलकुलेशन की बात है । अगर इतना पानी हमें मिल जाए तो खरीफ की फसल में 5.80 लाख एकड़ और रबी की फसल में 8.40 लाख एकड़ अधिक एरिया में सिंचाई हो पाएगी । जहां फूड ग्रेनड की बात है, अनाज 7.50 लाख टन ज्यादा पैदा होगा और 1.47 लाख टन आयल सीड पैदा होगा । 21.38 लाख टन शूगर केन पैदा होगा यह हमारा अनुमान है । अगर रुपये के बारे में आप सुनना चाहते हैं वह तकरीबन 107 छह करोड़ रुपये की ज्यादा फसल हरियाणा प्रदेश में पैदा होगी । (तालियां) मैं समझता हूं कि फारमज को जो फायदा होगा, वह नैट इन्कम 72 करोड़ की होगी । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिये यह

कैनाल, यह पानी कितना महत्वपूण' है । तो इस में देरी होने से चिन्तित होना हमारे सब के लिये स्वाभाविक ही है । अब बात केवल यह रह जाती है कि इस के लिये हम क्या कदम उठाए । हमें पंजाब प्रदेश के साथ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिये । वह हमारा बड़ा भाई है हम उससे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे और अगर फिर भी कोई बात नहीं बनी तो मैम्बर साहेबान की जो भावनाए हैं, और जो उन्होंने यहौ पर व्य–क्त की है मैं यह भावनाएं अवश्य प्रधान मन्त्री जी तक पहुंचाऊंगा इसलिय मैं इस प्रस्ताव के मूवर चौधरी मेहर चन्द जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें । जो बातें इस प्रस्ताव की आन सदन के सामने आई हैं उन सब बातों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा पूरी कोशिश की जाएगी । कु छ भाइयों ने यह भी शंका प्रकट की है कि सरकार ढीले तौर पर काम करेगी और मुख्य मन्त्री ढीले रहेंगे, इस बात के जिये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि हमारी तरफ से किंचित–मात्र भी ढिलाई नहीं होगी । जब तक कैनाल बन कर तैयार नही होगी, द्रुम आराम से नहीं बेटेने । आपको पता हैकल ही सप्ली– मेंटरी डिमांडज आपके सामने आई । शुरू में जब हमने साल का एनुअल प्लान तैयार किया तोकेवल 4 करोड़ रुपये का प्रोवीजन इसलिए कैनाल के लिये किया गया था और वह इसलिये किया गया था क्योंकि प्लानिंग कमिशन वाले इसके लिये तैयार नही हुए थे कि ज्यादा रकम दें । वे एक ही बात कहते थे कि आपके पानी का बंटवारा नहीं हुआ. पैसे का प्रोवीजन करवा कर आप क्या करेंगे और उन्होंने हमसे यह वायदा कर लिया था

कि जब भी बंटवारा हो जाएगा तो हम ज्यादा रकम जो आप चाहते हैं, मान लेंगे । हमने जो हिसाब लगाया है वह इस प्रकार है कि 19 करोड़ रुपया तो हम इस साल खर्च करना चाहते हैं, 33 करोड़ रुपया अगले वित्त वर्ख में खर्च करना चाहते हैं और जो बाकी 67 करोड़ में से बचता है वह तीसरे साल खर्च करना चाहते हैं । तो 15 करोड़ की नई डिमांड कल ही सदन के सामने प्रस्तुत की गई और आपने उसे स्वीकार करने की कृपा की । तो हमारी तरफ से किसी प्रकार से ढील नही होगी । जहां तक हरियाणा प्रदेश में कैनाल बनाने का प्रश्न है, हमने लैड एक्वायर करने की. कार्यवाही शुरु कर दी है । कुछ ऐसे सिविल वर्क्स के काम भी शुरू कर दिये हैं जैसे गोदाम बनाना, लोगों के रहने का इन्तजाम जिसकी स्टाफ को जरूरत पड़ेगी । इन सब कामों को हमने तेजी के साथ करना शुरू कर दिया है । पंजाब में काम तब शुरू होगा जब उनसे कोई बात तय हो जाएगी और मैं समझता हूं बात जल्दी तय हो जाएगी । अगर किसी कारणवश आपस में तय नहीं होगी तो हम प्रधान मन्त्री जी की शरण में जाएंगे । मैं आपकी भावनाएं उनके सामने रखूँगा और मुझे पूरी आशा है कि प्रधान मन्त्री जैसे पहले हमारी सहायता करती रही है उसी प्रकार आगे भी करती रहेंगी । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि चौधरी मेहर चन्द जी अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें ।

Chaudhri Mehar Chand : In view of the assurance given by the Hon. Chief Minister I with draw the resolution moved by me, but with the permission of the House.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the resolution ?

(Voices : Yes)

Mr. Speaker : The resolution is, by leave, withdrawn. The House stands abjourned till 9. 30 am tomorrow.

18.02 बजे

(The Sabha than *adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 19th July, 1976.)